Singapore. That is why export of cornet is increasing year after year.

The Union Government did not have a thorough study of the utility of this cornet and did not even ascertain the domestic need for the present as well as for future. The thoughtless mining will soon exhaust this rare mineral. Then, may be, India will have to import cornet for its use paying through the nose. This apart, the local problems and environmental aspects have not been taken into account. Cornet has not been subjected to latest tests to know whether it is radioactive. Even a little element of radioactivity will seriously harm the health of labourers involved in it. While permit is given only to take out a layer of the cornet for a few inches, the permit-holders dig up the coast for several feet, making the shore so deep that fishermen are not able to take their fishing boats into the sea. Because of these reasons, local people have been agitating against mining of cornet. Those innocent people have been booked under various sections and they are tortured. I appeal to the Government to drop all such cases against the innocent people and listen to their genuine demand.

Now, some 12 private concerns have been given permit for mining cornet. Over 70 more private concerns have applied for permit. Even recently, a Canadian company called Trans-world Cornet India Private Limited has been given permit to mine cornet for 20 years. If permits are given at this rate, this rare mineral will disappear from India very soon.

Therefore, I appeal to the Government to set up an expert committee to study the properties and use of cornet in India and also look into the problems the local people face due to mining. Till then, cornet should not be allowed to be mined in the interest of the people and the nation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, the House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty five minutes past two of the clock
The Vice Chairman (Shri M.D. Salim) *in the Chair*

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री विष्णु कान्त शास्त्री।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप धन्यवाद ज्ञापन के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा: जी, उसी पर निवेदन था। कल शास्त्री जी ने कहा कि 50 लाख पुस्तिका छपाई गई चारा चोर खजाना चोर पर। एक दिन का पूरा समय इनको मिल गया है। बताएं कि क्या यह सही है कि 50 लाख छपीं?

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे माननीय मित्र ने जो बात उठाई है, मैं और तलाश करके इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्नाटक): गवर्नमेंट को उत्तर देना है, आप क्यों देंगे?

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे कल, उसमें कई नए गुल आज के अखबारों ने खिलाए हैं। कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश के माननीय गृहमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के संबंध में जो मूल्यांकन किया है वह बहुत ही भयावह है और अगर वह सच है, ऐसा माननीय गृहमंत्री जी मानते हैं तो उन्हें अपने द्वारा नियुक्त वहां के राज्यपाल को बरखास्त कर देना चाहिए, लेकिन आज जो अखबारों में छपा है वह तो और भी विलक्षण है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने यह अभियोग लगाया है माननीय गृहमंत्री जी पर, कि उनकी तमाम उक्तियां गलत हैं। उन्होंने यह अभियोग लगाया है कि उन्होंने सही सूचनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेज दी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका

समर्थन करते हैं। एक अखबार में तो यह भी छपा है कि गृह मंत्रालय के लोगों ने माननीय गृह मंत्री की उक्ति का खण्डन नहीं किया। यह कैसी सरकार है, जिस सरकार के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही दृश्य को दो आंखों से देखते हैं? यह कैसी सरकार है, जिसके गृहमंत्री के द्वारा नियुक्त राज्यपाल उप गृहमंत्री की भर्त्सना करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय इन्द्रजीत गुप्त कैसे इस देश के गृहमंत्री बने रह सकते हैं? अगर उनमें रंच मात्र भी स्वाभिमान हो तो तत्काल उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का विश्वास उनको प्राप्त नहीं है, अगर उनके आंकलन को उनका अपना मंत्रालय चुनौती देता है, अगर उनके आंकलन को राज्यपाल चुनौती देता है तो यह दोनों बातें सही नहीं हो सकती, या तो इन्द्रजीतगुप्त जी सही हैं या राज्यपाल और प्रधानमंत्री सही है। एक मियान में दो खड्ग, देखा सुना नहीं था कैसे यह सरकार चल सकती है? मुझे मालूम नहीं।

महोदय, एक और करिश्मा इन राज्यपाल जी ने किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ नया युद्ध छेड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार को सक्रिय करेंगे। अब आप इस बात पर विचार कीजिए, सी०बी०आई० ने जिस आयुर्वेद घोटाले के कारण कुछ लोगों को चार्जशीटेड किया, जिन पर अभियोग लगाए, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार के तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उनमें तात्कालीन स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी हैं और हमारे माननीय राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हम उन पर अभियोग नहीं चलने देंगे। सी०बी०आई० के खिलाफ भी भ्रष्टाचारियों के पक्ष में राज्यपाल महोदय कवच बनकर खड़े होते हैं और यह तमाम मेरे मित्र इस सरकार का समर्थन करते हैं। यह तथाकथित वामपंथी, जो दिन रात भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हैं, यह तथाकथित कांग्रेसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कहने वाले, सरकार को उपदेश देने वाले हैं, लेकिन ये तमाम लोग उस राज्यपाल का समर्थन करते हैं, इस सरकार का समर्थन करते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल स्वामीनाथन जी ने इस पूरे तंत्र की विफलता की बात कही। यह तंत्र, यह व्यवस्था विफल क्यों होती है? यह तंत्र, यह व्यवस्था अविश्वसनीय क्यों होती है? क्योंकि यह तंत्र, यह व्यवस्था उत्पन्न करके कोई भी मंत्री एक दूसरे से मिलती जुलती बात नहीं करते हैं। यह सरकार इसके लिए अपराधी है। पूरे देश में आज इस शासन तंत्र के प्रति अविश्वास है।

महोदय, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गईं विजय निर्वाध जी की, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यंगकार भी है—

आप मरीजों की हालत का जिक्र कहां ले बैठे,
डाक्टर, नर्सों सहित यहां तो अस्पताल बीमार।

पूरा अस्पताल बीमार है, कौन किसका इलाज करेगा?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): पीठासीन हुईं

आप मरीजों की हालत का जिक्र कहां ले बैठे,
डाक्टर, नर्सों सहित यहां तो अस्पताल बीमार
सींग किसी के, पूंछ किसी की और किसी की टांगे,
सचमुच एक अजूबा ही है भारत की सरकार।

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं या कवि सम्मेलन कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब शास्त्री जी है तो कुछ कहेंगे ही।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आप सह नहीं पा रहे हैं, यह बात अलग है, लेकिन कैसी सरकार चल रही है, राष्ट्रपति किस सरकार की बात को कह रहे हैं? यह वह सरकार है, जिस सरकार का कोई मंत्री दूसरे मंत्री से स्वर मिलाकर बात नहीं करता। यह सरकार है? यह एक अजूबा है, और इसके आगे कहा गया है:—

रह-रहकर चौंका देती है घोटालों की खबरें,
यह बतलाओं ये नेता या.....?

आगे के शब्द मैं नहीं बोल सकता, अगर बोलूंगा तो माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया उसको प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानेंगी, लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि आगे के शब्द क्या होंगे?

रह-रहकर चौंका देती है घोटालों की खबरें,
यह बतलाओं ये नेता या.....?

कल मैं चर्चा कर रहा था बिहार के मुख्य मंत्री जी के बारे में तो मेरे मित्र बहुत नाराज हुए थे। मैं एक बार फिर उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप आज का "पायनिअर" खोलिए, उसमें बिहार के महा लेखापाल ने, कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जल संसाधन विभाग के एक बहुत बड़े नए घोटाले का भंडाफोड़ किया है। यह आज के "पायनिअर" में है, आप चाहें तो मैं आपको भेंट कर सकता हूं उसमें उन्होंने एक नए घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जो लोग इस देश का शासन चला रहे हैं, जो शासन का सबसे बड़ा दल है, उस दल के जो नेता हैं, जो बिहार के मुख्य मंत्री हैं, उनके

कारनामों में एक नया कारनामा उजागर हुआ है। मैं अपने मित्रों से कहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैं इसे यहां रख सकता हूं, पटल पर रख सकता हूं, आज का "पायनिअर" पढ़ लें। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार, यह सी० बी० आई० किस प्रकार से इस देश को सचमुच किसी अच्छाई की दिशा में ले जा सकती है? यह जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार के बारे में औरों की बात जाने दीजिए, इस सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने, इसी संसद के पूर्व सदस्य ने जो पुस्तक लिखी है, वह बहुत भयावह है और वह पुस्तक अभी तक प्रतिबंधित नहीं हुई, उस पुस्तक का सही-सही जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे लोग, जिस सरकार के बड़े-बड़े माननीय नेतागण इस प्रकार का अपना बिल्ला रखते हैं, वह उपदेश देते हैं कि भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं, मित्रो, "क्या कहें हम आज के इस लेख पर साहब, ...(व्यवधान)...

श्री हेच० हनुमनतप्पा: शास्त्री जी, उपसभाध्यक्ष जी को संबोधित कीजिए, यह पब्लिक स्पीच नहीं है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: महोदया, मैं कह रहा था:—

> क्या कहें हम आज के इस लेख पर साहब,
> इस त्याग और बलिदान के अभिलेख पर साहब,
>
> ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : आप किस विषय पर बोल रहे हैं शास्त्री जी?

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: महोदया, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार का विरोध करती है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपने किसी लेख के अभिलेख का उल्लेख किया, इसलिए मैंने पूछा है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: राष्ट्रपति ने कहा है कि भ्रष्टाचार का विरोध यह सरकार करेगी। यह सरकार कैसा विरोध कर रही है, उसी का नमूना पेश कर रहा हूं। जो लोग रात-दिन भ्रष्टाचार के विरोध का ढिंढोरा पीटते हैं, उनका चित्र कैसा है, मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूं। "क्या कहें हम आज के इस लेख पर साहब, इस त्याग और बलिदान के अभिलेख पर साहब, दिन-रात बोले आप भ्रष्टाचार के खिलाफ और आप ही रहे हैं नंबर एक पर साहब"। जो भ्रष्टाचार का परदाफाश होने पर नंबर एक पर खड़े हैं, वे ही भ्रष्टाचार का विरोध करने का नाटक करते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्था अविश्वसनीय हो गई है। इसलिए यह पूरा शासन तंत्र आज जनता की आंखों के सामने विश्वासघाती हो गया है। इसलिए आज लोग बार-बार जा रहे हैं न्यायपालिका की शरण में जिससे कि कार्यपालिका और सरकार का जो आचरण है, उसको उघाड़ा जा सके।

महोदया, मैं एक बात बड़ी पीड़ा के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी इस नयी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की बंगला देश के साथ। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि बंगला देश के साथ सौहार्द हो, इसका मैं समर्थक हूं। "मैं तुम्हारा स्नेह, संवेदन ज्यादा चाहता हूं, पर नहीं उस दाम पर जो मंगले तुम"।

महोदया, बंगला देश के साथ समझौता हो, बंगला देश के साथ सौहार्द हो, मित्रता हो, यह हमारी भी इच्छा है लेकिन क्या यह मित्रता कलकत्ता और हल्दिया की लाशों पर होनी चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि यह समझौता किस प्रकार हुआ? महोदया, 12 दिसंबर, 1996 को जो समझौता हुआ है, उसमें आंकड़े 1988 के हैं। यानी 1988 के आंकड़ों पर 1996 में समझौता हुआ है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री इस समझौते में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री मेरे मित्र हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे मेरे सहयोगी रहे हैं और मैं उनकी विद्वता पर गर्व करता हूं लेकिन मैंने पढ़ा है उनके लेख को जिसमें असहाय स्वर में उन्होंने कहा है कि चूंकि बंगला देश की सरकार ने कहा कि उनके पास 1988 के बाद के कोई आंकड़े नहीं है, इसलिए मुझे लाचार होकर 1988 के आंकड़े स्वीकार करने पड़े। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। बंगला देश की सरकार के पास 1988 के बाद के आंकड़े नहीं हो सकते, यह संभव है किंतु क्या पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री के पास भी ये आंकड़े नहीं थे? क्या पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री को भारत सरकार ये आंकड़े नहीं दे सकती थी? क्या पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, बंगला देश के प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों को विश्वास नहीं दिला सकते थे कि ये वास्तविक आंकड़े हैं? महोदया, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): शास्त्री जी, आपकी पार्टी के पास समय है एक घंटा, सत्तावन मिनट जिसमें से आपने लगभग डेढ़ घंटे का समय ले लिया है। आपकी पार्टी की ओर से 3 वक्ता और है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: अच्छा, मैं संक्षेप में बोलता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अगर आपकी पार्टी के बाकी लोग न बोलें, तो आप बेशक पूरा समय ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जो पड़ोसी राष्ट्र हमारे देश के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता, उससे दोस्ती कैसे हो सकती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1988 में फरक्का में जो पानी था, क्या वह 1996 में था? क्या वह 1995 में था? क्या वह 1994 में था? मेरा आरोप है कि नहीं था। मेरी अपनी सूचना है कि 1988 की तुलना में 1996 तक आते-आते फरक्का में बहुत कम पानी रह गया है। जो समझौता इन्होंने किया है, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने बताया है कि सूखे के मौसम में 81,854 क्यूसेक से लेकर 60,992 क्यूसेक तक पानी वहां रहेगा। ऐसा 1949 से 1988 तक के औसत आंकड़ों पर निर्भर है। सच्चाई यह है कि सूखे के मौसम में मार्च-अप्रैल में वहां 50 हजार क्यूसेक से भी कम पानी रहता है। पारदर्शिता के ऊपर यह सरकार बहुत ढिंढोरा पीटती है। माननीय विदेश मंत्री यहां पर हैं। पारदर्शिता के नाम पर मैं उनसे अपील करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री हमें बताएं कि वहां पर 1996 में कितना पानी था, 1995 में कितना पानी था, 1994 में कितना पानी था वहां। 1994, 1995 और 1996 में लगातार घटते हुए पानी के बावजूद 1988 के आंकड़ों पर समझौता कैसे होता है? यह केवल हमारा ही देश कह सकता है कि 1988 के उस आंकड़े में जितना पानी है वह पूरा का पूरा पानी वहां पहुंचाने के लिए भारत सरकार उत्तरदाई रहेगी। मैं पढ़ना चाहता हूं—

"Every effort will be made by upper riparian to protect the flow of water at Farakka as in the 40 years average availability as mentioned above."

1949 से 1988 तक जो पानी वहां था-आंकड़ा औसत, वह 1997 में भारत सरकार उपस्थित करेगी। कैसे करेगी? मेरे बिहार के मित्र यहां बैठे हुए हैं। बिहार में जनता दल की सरकार है। बिहार के सिंचाई मंत्री ने प्रतिवाद किया है इस समझौते का। बिहार के सिंचाई मंत्री ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके कहा है कि इससे बिहार की तमाम सिंचाई योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राग-रंग करने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है कि वह इस विषय पर सोचें। उत्तर प्रदेश ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में हमारे किसानों ने लगातार पम्प लगा-लगा करके जो सिंचाई की है उस सिंचाई के कारण 1988 और 1996 के उपलब्ध जल में बहुत कमी हो गई है।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): I want to submit a technical point with regard to hydrology.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वहां तब न पानी होगा ऊपर से पानी फरक्का में आएगा।

DR. BIPLAB DASGUPTA: If you do not allow me, I will sit down. ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Dr. Dasgupta, you address the Chair and not the hon. Member....*(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, with your permission I would like to submit that from the point of view of hydrology water flows from high altitude to low altitude. Now, this may be affecting West Bengal. ...*(Interruptions)*... But how it can affect Uttar Pradesh, I am not able to understand. How will the water meant for Uttar Pradesh be reduced? This water goes from Uttar Pradesh down to West Bengal. It never flows up from Bengal to Uttar Pradesh. I do not know whether the BJP has a different kind of hydrology. ...*(Interruptions)*... That is our problem. ...*(Interruptions)*... That is not your problem. ...*(Interruptions)*... Do not mention U.P. and Bihar.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मुझे बोलने दीजिए। 1996-97 में पानी भारत सरकार देगी। कैसे देगी? अगर उत्तर प्रदेश के, अगर बिहार के, अगर पश्चिम बंगाल के किसान भाई उसके पहले लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा गंगा से पानी लेते रहते हैं और गंगा में पानी कम पहुंचता है तो 1988 में जितना पानी था कहां से 1996-97 में उतना पानी आएगा और फिर दूसरी बात ...(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): जो एग्रीमेंट है उस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में जितना वहां

पहुचेगा। ऑल परसंटेज हमने वर्कआउट की है, डेटा उसमें सारा दिया है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: उसमें लिखा है: "Every effort will be made by upper riparians to protect the flow of water...." आप ने इसको बांधा है। आप पढ़िए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश और भी अधिक इस्तेमाल कर सकता है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह पानी कैसे सुरक्षित करेंगे। अभी कानपुर में जो बांध बनने वाला है जिसकी स्वीकृति हो गई है, क्या आप उसको रोक देंगे। आप क्या उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के किसानों को जल सींचने से रोक देंगे। कैसे होगा पानी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ इतनी बात नहीं है। इस समझौते में बताया गया है कि जो फरक्का में पानी आएगा सूखे मौसम में बंगला देश के लिए जितना पानी दिया गया है उसका 90 प्रतिशत पानी उसको देना पड़ेगा। 90 प्रतिशत पानी देने के बाद कलकत्ता के लिए कितना पानी बचेगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों फरक्का बांध बनवाया गया? 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में व्याख्यान देते हुए कहा था कि हमें कलकत्ता बचाना है, कलकत्ता बचाने के लिए हम फरक्का बांध बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बांध भारत सरकार ने अरबों रुपए खर्च करके इसलिए नहीं बनवाया था कि थोड़े से तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए हम अपने देश को, कलकत्ता को और हल्दिया को बिल्कुल व्यर्थ करके बंगलादेश के साथ समझौता करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसा समझौता हुआ है? कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के साथ बात नहीं हुई है। डॉ॰ विक्रम सरकार ने उसी पर आपत्ति की है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी गए, बंगाल के वित्त मंत्री जी गए, पोर्ट कमिश्नर के साथ, फरक्का के किसी अधिकारी से बात नहीं हुई। किसने उनको यह बताया कि 40,000 क्यूसेक पानी चाहिए? 40,000 क्यूसेक की जगह वहां 20,000 क्यूसेक, 18,000 क्यूसेक पानी जाएगा। कैसे अभी कलकत्ता मर रहा है? बड़े जहाज अभी कलकत्ता बंदरगाह पर नहीं पहुंच पाते हैं। जितनी मात्रा में कलकत्ता बंदरगाह में ज्वार के साथ आई मिट्टी जमा होती जाएगी पत्थर की तरह, उतनी मात्रा में उसकी गहराई कम होती जाएगी। कैसे हमारा कलकत्ता बंदरगाह जीवित रहेगा, मैं जानना चाहता हूं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हल्दिया कैसे बचेगा? आखिर हमने किसलिए फरक्का बांध बांधा था? मैं इस विषय में बहुत विस्तार से बोलना चाहता हूं, मुझे बहुत सी बातें इस पर कहनी हैं। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है, मैंने इस पर विशेष बहस की मांग की है। मुझे विश्वास है कि माननीय विदेश मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और इस पर सभी दलों के लोगों को खुल कर बात करने का मौका मिलेगा लेकिन मैं यह मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री ने और भारत सरकार ने कलकत्ता की छाती पर छुरा भोंक दिया। बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, मैं इस सम्माननीय सदन में यह बात घोषित करना चाहता हूं।

मैं दो-तीन बातें और बोल कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। कश्मीर के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं लेकिन उन तीन लाख अभागे कश्मीरी पंडितों के बारे में एक शब्द इसमें नहीं कहा गया जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भारत सरकार की सदस्यता पर विश्वास किया और अपने ही देश में जो परदेशी बन गए हैं, अपने ही देश में जो शरणार्थी हो गए हैं। इस देश के किसी प्रधान मंत्री को इतना अवकाश नहीं मिला है कि उन तीन लाख पंडितों के शिविरों में जा कर उनकी हालत देखें। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री को भी नहीं मिला है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस व्याख्यान में राष्ट्रपति जी ने "धर्मनिरपेक्षता" शब्द प्रयुक्त किया है। धर्मनिरपेक्ष, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही भ्रामक शब्द है, बहुत गलत शब्द है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के इस व्याख्यान के लिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, उन्होंने दंडनीय अपराध किया है। "सेक्युलर" शब्द का अनुवाद हिन्दी में "धर्मनिरपेक्ष" नहीं होता। "सेक्यूलर" शब्द का प्रामाणिक अनुवाद केवल संविधान में पाया जा सकता है और संविधान में "सेक्युलर" शब्द का अनुवाद किया गया है "पंथनिरपेक्ष"। कैसे "पंथनिरपेक्ष" शब्द के स्थान पर "धर्मनिरपेक्ष" शब्द का प्रयोग किया गया, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहा गया है:—

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा

और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए...."

भारतवर्ष में "धर्मनिरपेक्षता" अचल शब्द है। मैं जिस सम्माननीय सदन में बैठा हुआ हूं, उसके प्रधान द्वार पर लिखा हुआ है "सत्यं वदः धर्मम् चर"। जिस लोक सभा का सम्मान सारा देश करता है, उस लोक सभा के अध्यक्ष की पीठ पर लिखा हुआ है "धर्मचक्र प्रवर्तनाय"। जिस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सारा भारतवर्ष शासित होता है, उस सर्वोच्च न्यायालय में लिखा हुआ है "यतो धर्मः ततो जयः"। ...(व्यवधान)...

3.00 PM

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: इससे यह चाहते हैं कि हम निरपेक्ष हो जाएं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: यह देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? ..**(व्यवधान)**...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: इससे हम निरपेक्ष हो जाएं। आप तो हो ही गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका पुनर्मुद्रण हो और राष्ट्रपति जी के व्याख्यान में से धर्मनिरपेक्षता को हटा कर पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाए। यह बहुत बड़ा अन्याय है और संविधान का अपमान करके हमारे राष्ट्रपति कैसे सद्व्यवहार कर सकते हैं? तो कैसी यह सरकार है जिस सरकार को अपने संविधान के प्रामाणिक शब्दों का भी ज्ञान नहीं है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं राष्ट्रपति जी को एक दूसरे मुद्दे पर सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा लिखी गयी पंक्ति को उन्होंने काट दिया है। इस मुद्दे पर मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो 12 नाम उनके पास भेजे गये थे, जो तथाकथित राजनैतिक नेता थे, जिन राजनैतिक नेताओं को पिछले द्वार से राज्य सभा में घुसाने की चेष्टा यह सरकार कर रही थी, कलाकारों के नाम पर, साहित्यकारों के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार के ऐसे दुराचार को उन्होंने कहीं तो नियंत्रण लगाने की चेष्टा की है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के वर्तमान अभिभाषण का विरोध करता हूं और मानता हूं कि किसी भी प्रकार से उनको कोई भी धन्यवाद देने का इसमें कोई कारण उत्पन्न नहीं होता। नमस्कार। धन्यवाद।

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Madam Vice-Chairperson, I stand here to support the Motion of Thanks on the President's Address. Our President has, over these five years in the Rashtrapathi Bhavan, added a great deal of dignity to the office of the President.

I know that last year, we hardly had an opportunity to thank the President for his Address because, as you know, the thirteen-day Government had presented the President's Address, but nothing could be done after the Government fell. Therefore, it is after a long time that we are really having a meaningful debate on the President's Address.

I see that a lot of things have been said. A lot of commitments have been made. But I would like to ask whether it is at all possible for the Government, with the type of different groups which are seeking to implement what they have committed themselves to do; whether it is going to be possible at all for them, to do even half the things which they have mentioned in the President's Address.

I believe the Government, today, is essentially a Government based on the politics of survival. That means, it is a Government of compromises. If the Left says: 'yes', someone else says: 'no'. If the Left says:'do this', someone among the regional parties says: 'no'. Given the circumstances, I do realise that it is not an easy job for the Government, particularly, for the Prime Minister, to be able to strike a balance between others and those who have pressing regional interests which dominate over national perspective and national interests, for the simple reason that they have only been elected on the basis of regional and local manifestos.

Therefore, when the Government came up, ultimately, with the so-called CMP, the Common minimum Programme, there was a great deal of expectation and also a

great deal of relief among many of us that these fourteen parties—sometimes, it becomes thirteen; then it goes up to 14; I do not know what is the exact number today; I think it is again 14—had, at least, agreed on a common minimum programme. But the point is, you came out with your Common Minimum Programme. Whatever the President's Address might have committed, what I really want to know is: what has happened to the commitments made in the Common Minimum Programme?

When you have a Centre which is not very sure of itself, when your indicators are showing a sliding economy, and when you have a general diffidence, if I may say so, in pulling the different parties together, I must say that the administration of such a Government, undoubtedly, suffers. It is not that you are not trying —we agree that you have problems. But the feeling that goes out is that you are not quite sure of what you are going to do tomorrow. It seems to be survival from one session to other: "Let's keep everything aside; let's not worry about what happens next year; let's just see that this session is gone through and what is before us is the least controversial so that we don't take decisions which might upset anybody."

Madam, the saying in the corridors of the Ministries in Delhi is that most Ministers seem to be on tour to Delhi in the sense that they would rather spend all their time in their States because they have, essentially, commitments to their regional parties and their local issues than sit in Delhi and be here full-time Ministers. There are exceptions, but this is what the officers joke and say, "Madam, we have Ministers who come on tour to Delhi?" And this is the feeling that goes, that there isn't that kind of a grip on the Administration which is so important in a country of this size with the type of problems which we are facing.

Madam, I would just talk about two things before I go into the Address itself. In every single session in the past, when we were sitting there, there used to be a noise on the first day about Ordinances being issued and about our taking Parliament very lightly. I go only to one Ordinance, and I take very strong exception to this, that is, on the sugar exports. It was very clear in this House—though the Lok Sabha had some objections from the Congress, it passed the Bill—that we were not prepared to let it go through, on the last day of the last session. it was, in fact, at my intervention at one level that we said, "Let's not get into any hassles now, let's defer the Bill and let's have consultations and come back." That was agreed to, and the parliamentary Affairs Minister who rushed here gave that assurance. But what I see now is that immediately after that an Ordinance has been passed and, when that Ordinance has been passed, what the statement placed here in the House says is, "The Rajya Sabha considered the Bill on so and so date, but in view of the paucity of time the consideration of the Bill was deferred." It was not for paucity of time but it was because we said that all of us here would not allow the Bill—we were going to defeat the Bill—that it was decided as a compromise that it would be deferred. And then you have passed the Ordinance and now you come with a fait accompli and say, "Well, it is there now, and please help us pass it."

Madam, I am here with this report which has appeared in the Indian Express on 20th February: "Fraud alleged in sugar decanalisation." The whole question of this decanalisation has been discussed and it is very clearly pointed out that though you came with the ordinance, the first announcement was made on September 22nd by the Food Minister. The announcement is made, you give an indication that you are going to decanalise so that all those who are in the business, in the trade, have time to do what they want to do and make money. It is very clearly pointed out here that there has been a loss of Rs. 42

crores to the national exchequer because of this single decision, the delays after the issue of the Ordinance—and you have said in this that it was so important that you had to do it. The report very clearly says that even confirmed contracts of 2.5 lakh tonnes of sugar to Indonesia didn't go and in the international market you had the Thais make money out of higher prices because India was out of it. No orders as yet have been passed; the required administrative orders are still not passed to allow sugar to be exported. Where was the need for the ordinance if you still haven't passed the administrative orders which are required to implement what you said you were doing? Then, what was the emergency to have the Ordinance?

Who made the money? Who was behind this? I am not naming anybody here, but a lot of facts will come out, a lot of names will be mentioned. I only say that Ordinances are for an emergency. If it was so important, how is it that the—I quote here—"apex body through which exports would be routed, took one whole month to clear the procedures to be followed? This was decided only on February 17. The APEDA has still not released any trade notifications in the major newspapers as is the normal practice." Then it says:

> "Going by the record of the present Government, it will be at least another month during which decisions would have to be taken."

Then, why the Ordinance? Was it just to give advance warnings and advance signals to people what was coming so that everybody could make money in the meantime?

Madam, I also want to say that pre-Budget announcements are being made indiscriminately. You are in the Budget Session. Just two weeks before the Budget, Mr. Chidambaram, your Finance Minister, announced amnesty for MODVAT defaulters. Rs. 8,000 crores have been given away by adminstrative orders. The original scheme was introduced here. It was passed as part of the Finance Bill. You amend it. When the Budget Session is coming, you give all these concessions by the administrative order! We are told that it is a *fait accompli*. Rs. 8,000 crores are involved in it. Who has benefited by it? For whose benefit was it done? I am not going to take time on this now because this is not a debate on the Budget. But, it will all come out during the debate on the Budget. We have all the facts. Therefore, I am asking the basis on which we are talking about the great, big commitment in the CMP to fighting corruption.

You have thrived on calling everybody else corrupt. You are prepared to put former Ministers and Prime Ministers in the dock and say that everybody is corrupt. Within not even a year but within a few months you have these mounting skeletons which are all going to come out. For ten years you went on Bofors. You made charges and counter-charges and any number of campaigns in the country. yes, we lost the Government. We paid the price. But, when I was there, I repeatedly used to say, "We want the papers. We want the truth to come out because we knew all along that Rajivji was not involved in it."

And who gave the assurance in February, 1990 to the Swiss Government? Who signed the understanding that no names would be released? I was no less a person than Mr. V.P. Singh and his Government.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Actually the agreement was arrived at in 1989 February.

SHRIMATI MARGARET ALVA: No. I am sorry. I have the facts. Don't challenge me on this.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The first undertaking was given in 1989 February during the Rajiv Gandhi Government. Let the Government give the document., In 1989 when Mr. Rajiv Gandhi was the

Prime Minister, the undertaking was given.

SHRIMATI MARGARET ALVA: let the Prime Minister reply. You are not the Prime Minister. ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Dr. Biplab Dasgupta, kindly take your seat. You can make your point when you speak. Don't interrupt now. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI MARGARET ALVA: If I am wrong, let the Government prove me wrong. You are not the spokesman of the Government at the moment. I appreciate your desire to defend the indefensible. ...*(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am giving the fact. In 1989 February when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, the memorandum of understand was signed with the Swiss Government. An undertaking was given to the Swiss Foreign Minister that the papers would be used only for investigation purposes. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI MARGARET ALVA: We have got all the names. Okay, let them come up. Place it on the Table. Don't make your false propaganda. Place it on the Table if you want to challenge me. ...*(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: It was signed in 1989 February when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI MARGARET ALVA: it is not this government. They have not translated the papers yet. I don't think that any of them sitting here know French. Please be very clear about it. The papers have not yet been translated.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Let them do it. It was done in 1989 February, not in 1990.

SHRIMATI MARGARET ALVA: If you know this, lay it on the Table of the House. ...*(Interruptions)*

I am coming to the point. CMP or no CMP, each member of the Government seems to be having a different stand on different issues. I just mentioned Bofors. On corruption itself, I want to know this. We have talked so much about cleaning up the system. You have repeatedly talked about the Lokpal Bill. You challenged me when I was the Minister in charge of the Lokpal Bill. The draft Bill was ready. At the last moment, the BJP said, "The outgoing Government has no business to bring a Bill. let the new Government do it." You don't even have to do the homework. If you have to draft the Bill, I know it is going to take two years. The Bill is there. Why don't you have it passed? You have 14 parties. The BJP is supporting it. We are supporting it. Everybody else is supporting it. You wanted the prime Minister to be included in it. We have included the prime Minister in it. Why don't you bring it?

THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Madam, on this particular question of introducing the Lokpal Bill, P.M. has met with all the leaders over a discussion in the Speaker's Chamber. The hon. Prime Minister has made it quite clear that this Government is intending to introduce the Bill.

SHRIMATI MARGARET ALVA: We all know you are intending to do a lot of things.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The Prime Minister has said about the Lokpal Bill and about the Bofors documents. he is clear about everything without doing anything.

DR. D. VENKATESWARLU: Madam,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Minister, there is no need of your intervention at this point of time.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You bring the Lokpal Bill. We are glad that you are going to talk about it in a committee being set up by both the Presiding Officers, but what we are pointing out is when you can bring an ordinance on sugar, when you can bring all sorts of incorngruous Bills, why don't you come with the Lokpal Bill on priority because you can pass it without any debate? Where is the need to call the leaders to sit in your Chamber? Come to the House with the Bill. Those who are to oppose it, will oppose it on the floor of the House. All the consultations with political parties have been held in the past. That is how the draft came. We are saying bring the Lokpal Bill. Let there be something on which you can say, "it is here now. We have started the fight on corruption." Instead of that, you are indulging in mud-slinging and every such thing.

Electoral reforms was another issue. I am glad that Gujral Sahib is here. Repeatedly you raised the issue on electoral reforms. A Committee report headed by the erstwhile Law Minister, Shri dinesh Goswami, was submitted by the earlier Government. You were charging us that we were not serious. Now, you have the report on electoral reforms and other things. Come with basic reforms, since you have the power and authority now. Do what you have been wanting. Do it quickly. Otherwise, you may not have the chance. Let us see it happen. Why is it not happening?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Are you going to topple?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, I am nobody to topple. I am only saying that the time is running out of the hands of the United Front Government. Let us be very clear that this is something which cannot be played around with. Let us, as a nation, make a commitment and start somewhere. We also want it.

I would know talk about the question of a Judicial Commission. I have spoken on it before in the House and I do believe that the Constitution-makers were clear about the checks and balances in the Constitution to ensure that there would be no aberration. We are very clear that each one has its role and each one has to play its role. Who is to appoint judges, what is to be done, how far each wing can go, are issues for deciding I believe the forum which has the authority of the people is the elected chamber of Parliament. It has to have the final say. Why are we afraid? Let us decide how far and where we can go on these issues. Let there be no confusion or pulling in opposite directions. These issues have to be settled by us cutting across party lines in a responsible manner. The Judicial Commission issue has been mentioned before and appointment of judges has been discussed before. We would like to know what the Government's reaction is today. What do you intend doing?

The whole paragraph 7 of the President's Address has spoken about fighting corruption. Madam, there is another great thing. I am again coming back to sugar export. Why did we export it? Let me be vey clear. Just some time ago, you exported wheat saying you had a surplus of wheat. So, you released a certain quantity of wheat and sent it out. In no time you said that you were short of wheat and you have to import it. You imported it at a much higher price. Who made money on both the sides? Here are a number of articles written by experts demanding a CBI probe.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Your Government also exported 9 million tonnes.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: One wrong does not justify another wrong.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Then why did you say it was wrong? You charged us. I am just saying, don't think that you are all saints. I am glad that you have learnt some good things from us. Now learn some more good things also

and keep quiet. It is very clearly said here, "kickbacks at the rate of Rs.100/- per quintal" and "ten lakh tonnes of wheat to exporters at the rate of Rs.490 per quintal was released when the market price was Rs. 800 per quintal." And all this information is given by the FCI workers. You are all workers' champions. They have circulated it to all the Members of Parliament. At least I have received copies asking us to see what has been happening with these releases. It was the FCI workers Union who first came out with all the facts and figures. They say in Haryana alone it was Rs.400 crores and if you take the whole country, it would go to almost Rs.4,000 crores. What is happening? Does anybody know what is happening in each wing of the Government? It was easy for you to blame everybody else. What are you doing today? Where is your fight against corruption which you talked about all the time? Yes, we have paid the price. We did not control things. We have made mistakes and we have paid the price. But for Rs.64 crores of "Bofors scandal" you ran wild around the country. What is happening in Bihar? What is the financial emergency in Bihar? According to the CAG's report, it is Rs.4,000 crores or more. I am not going to name anybody. I am saying why do you have one set of rules when it comes to one set of people and political parties? Today there is a shocking report in the newspapers. I am not saying it. There is a report of a raid on the Mescos. I hold no brief for anybody. But the Income Tax Officer said that there was a donation of Rs.3 crores to the Congress party which we have stated in our returns of the political party. This has led to the raid. You say, "File your income tax returns." We told you who has given us donations, you raid them. You raid your political opponents who are funded. You take away everyone of their books and say that we are corrupt. How do parties file their returns now? The Income Tax Officers said that donations of Rs.3 cores to the Congress party led to the raid. What is the crime if we have mentioned it in our papers? Yet the CAG's report mentions about the bitumen scam, the animal husbandry scam, the fodder scam, the water resources scam and every single thing you can name. Crores of rupees have gone down the drain in Bihar.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Gone into pockets, in Bihar.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry. That money has gone into pockets, not down the drain.

But my point is you don't give permission to file chargesheet which are ready for the last two months. We know that the chargesheet is ready. We know the names in the chargesheet. But you are not giving clearance. It has been reported that the great Mr. Joginder Singh carried a camera in his pocket at the time of his receiving Bofors papers so that somebody could take a picture of his for record.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it would be better if she doesn't take the name of the official.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Okay. the Director of the CBI comes on TV every night. His name has become more important than the T.V. stars in the country. He is on T.V. giving statements outside the Supreme Court and in his office which was never done in the past. I am sorry to say that. Every code has been violated. An investigating agency is supposed to be doing secret work.

SHRI VISHNU KANT SHASTRI: He is being used to blackmail other political parties.

SHRIMATI MARGARET ALVA: An investigating agency is supposed to do secret investigation but not television interviews every night and leaking out selective information. Whom does it help? then, we said, come out with everything. You say, "We are bound by agreements." Then, why are you selectively leaking out? Just to get

political benefit you are blackmailing political parties and individuals. Is that what the CMP is all about? I want to ask the Government: Are you fighting against corruption?

Madam, now I come to the contradictory statements. A lot of things have been said. I quote from the President's Address, "Under our democratic federal polity, coalition Governments can be stable and promote durable socio-economic development." I am not challenging the President's statement. But what do we see? Take Uttar Pradesh. Shastriji has spoken about it. A number of my colleagues have also spoken about it. The Home Minister of this country makes a statement about the law and order situation in a State. Madam, a Governor had the cheek to go the Press to challenge the Home Minister of this country. He said that what the Home Minister had said was wrong. So far the Government did not react to it. If I were the Home Minister of this country, I would have said that the Governor has to go home this morning or else I would go. Nobody has reacted. Madam, what is more insulting is that the Governor had the cheek to say, I am sorry to say this. I am not supposed to use such words against Governors I am quoting from the Press statements. He said, "...but the Prime Minister is happy with my work." As if to you say, "I don't care for the Home Minister's opinion." What is happening? Is it a divided house? The Home Minister and the Prime Minister together must decide what is happening and how it should be put right.

You take the question of Jammu and Kashmir. I have great regard for the Chief Minister and his party, the National Conference. They have fought long battles with us; for the country, I mean, over these years of problems in Jammu and Kashmir. He says the line of actual control must become the final thing. Somebody else in the Government says something else. Each of them says a different thing. Do your have a policy? What is happening? What are the signals you are giving on Jammu and Kashmir? The Prime Minister says "minor adjustment"; somebody says "the line of actual control"; other parties say "nothing doing". What is happening? Madam, time and again, we have seen these contradictory statements on insurance. some of them say "no opening up"; others say "it is inevitable". You take the question of foreign airlines. Two Ministers are quarrelling in the Cabinet whether the Tata-Singapore Airlines venture should be on or not. One says "temporarily deferred"; somebody else says, "I will not allow it to come". What is happening? you do not worry what happened two years ago. Think about today. What are you doing? Come with a policy. Say, "Yes, we are for it" or "No, we are against it". You cannot agree on what your policy is. How can you agree with the policy.....(*Interruptions*). You are the only ones who defend them. It is better you at least get a ministership. You will at least have the status of being partners. You cannot have all the benefits of running with the hare and hunting with the hound. (*Interruptions*). You want it both ways. Make up your mind as to what suits you. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Don't interrupt. Let her continue. (*Interruptions*). Please do not interrupt.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The Address has been presented by your Government, not by my Government. so, I do not have to defend my policies.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): You do not have to react to their comments.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, they should not interrupt.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): You go on. You do not look at them.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry, Madam. They are not worth looking at. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please set down, Mr. Baby.

SHRI M.A. BABY (Kerala): We cannot help looking at her, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): You go on looking at her. But let her continue.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, power without responsibility is the worst from of corruption. (*Interruptions*).

I am asking again about the nuclear power plants. Gujral Saheb is here. We have been opposing any kind of inspection, any kind of foreign agency meddling with our nuclear power plants or programmes and our nuclear energy programmes. Madam, in the last Session, when I asked a simple question in this House on Kaiga where the dome had collapsed and there was an agitation in North Kanara, both the Minister and the Prime Minister said that they could not even give the details, the engineering details, of our power plants or projects becuase they were confidential and they were never disclosed. I had gone there. I had inspected the place. We had promised that the report would be made available to the local people because they were afraid of nuclear pollution which was none. I said, "Let us release the report, let the people at least know". We were told it could not be done. The next thing here, the Prme Minister announces that we will allow multinationals, international consotiums, to come and set up nuclear power plants in this country. From where is the fuel going to come? Who is going to submit them to what kind of control, to what kind of regulatory conditions? Is it or is it not going to be a backdoor admission that international agencies can come here, inspect our nuclear plants? you cannot say, "You go there; come here; you cannot go there; you can do this." You are opening up everything to them and then talking about the CTBT. What are we talking about?

SHRI I.K. GUJRAL: Could I explain?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not confusing. I know they are two different things. Mr. Gujral, you are an expert. I am only saying that we take such firm stands on the one hand that we are sovereign and supreme and we will take our decisions. We stood by them. I stand by them. I congratulate you. In fact, I am coming to you on foreign affairs. Twelve paragraphs of the President's Address, out of 52, deal with foreign affairs. You seem to be the only Minister who is delivering the goods.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: It is a fact also.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It is a fact. And we congratulate you because you seem to be the only performing Minister. After all, given your background, you are where you are because of your ability. Madam, I am asking the hon. External Affairs Minister: How happy are you about a policy statement allowing international interference in your nuclear energy programmes in the country? I know you are not happy and I do not expect an answer from you.

Madam, I can tell this from his smile. I am coming to the other questions. Again, I come to the 'CMP'. they may be very happy to have the foreign companies come for nuclear power plants in Bengal. They can defend it. I am not bothered about it. Madam, I am now talking also about the Women's Bill, another part of 'CMP'. You made a commitment. You have made a commitment again yesterday which has been widely publicised and I am grateful to you. This is not an issue of men and women. We are talking about commitments that have been made to 50 per cent of the population, to give us a place in the power structure, in the

decision-making forum. We are not saying that there can be a consensus. There cannot be a consensus on Foreign Policy. Someone says Farkka is good, someone says Farakka is bad, someone would say Jyoti Basu did the right thing. Someone would say that someone else did the right thing and some one else would say something else. But ultimately we come to some conclusion. But you do not want to discuss the Bill in the House or put it before the House. Let it be defeated. I want it to come to the House. I want it to be debated and defeated. If they bring it before the House, let it be defeated. Let the country know that this Parliament is not yet mentally and emotionally prepared to accept women as an equal partner in politics. But let us not go and make statements in international conferences and spend crores of rupees to publicies our great commitment to partnership and then run away from it. मैंने कल कहा कि छुपे हुए रूस्तम, जो पर्दे के पीछे से ही इसको रोक रहे हैं, उनको बाहर निकालिए।

Let them come to Parliament and vote and let the people and their constituents, particularly, women know what their stand is in Parliament. I know what price Mr. Kamal Nath paid for making his wife give up the seat for him. The women and the people of this country also know that women have to have a place in the home and outside. Don't think we can just be treated like commodities in the market place. Women's movement as come of age and if this Government today goes back on its commitment, I say this, with responsibility, you will pay the price of women's discontentment in the months ahead.

SHRI I.K. GUJRAL: I congratulate you for championing women's cause.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Okay, I am glad for that. This is what I am talking about the 'CMP' and all the commitments that have been made. in para 50, the President has made a commitmet and spoken about the same Bill in the Address. We have specially market this para and made copies of it. How serious are you about passing it? It is not listed among the 78 Bills which have come. Madam, my party has some time. So, I am going to take another ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRIMATI KAMLA SINHA): All right. You go ahead.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Then I come to the question of liberalisation. I know you will immediately say, Congress legacy. Yes, it is a Congress legacy, and you have taken over the Finance Minister, who is also the Congress legacy for you to make sure that there is continuity. I am saying that I am not against investment coming. Let them come. We need to create jobs, we need to create the infrastructure, we need to modernise. Everything, yes. But I am putting a question. How many jobs have been created with these investments? Have jobs been lost or have jobs been created? Then I come to the Exit Policy. I do not know who is looking at what. All I know is that these multinationals who are coming and huge investments which are coming, most of them are going into buying Indian companies. What is coming is not investment for new industries. The infranstructure is not being created, the core sector is not growing. We have got consumer durables, consumer items, everything that has to be thrown out after one year. So more can be produced. We are launching overselves into a consumer society which is going to drain our nationaal resources and which is going to create more and more imbalances between the 'haves' and 'have-nots', and therefore, I am saying at this initial stage itself, all of us, cutting across party lines, have to look upon what this policy really has to be, how far we can go, and how and where the control has to be applied.

Everybody is quoting China to us. The Chinese system is not the same. There

are controls and checks which keep everybody within the limits and the parameters which they set. Are we doing it in this country? Do we know who is coming and doing what? In every State, lakhs and lakhs of acres of agricultural land is going into industry. Huge amounts are being paid. Around Bangalore, everything is being sold and the land mafia is growing outside every urban centre and around every industrial development area. I will give figures now of the slide down in food production. It is not worthwhile keeping your land and struggling when you can make your money and invest it with some company and get your returns. Are jobs being given to those who have been displaced? Are there guarantees that the land which is acquired is not going to be just for the sake of buying up land? Take, for example, the Bangalore airport. One thousand acres or two thousand acres of agricultural land is being demanded. You are supposed to acquire the agricultural land and give it to them for the international airport. You have the HAL airport in Bangalore. Enough of investment is taking place even today on the runways and infrastructure. Can't the HAL be moved out from Bangalore? Only the hangars have to move out. The HAL factory can move out. The same airport can be extended. The land is there. As far as the policies of the Government and of my party's commitments are concerned, I may sound a little, I don't know, not on the correct note. But I am saying that every multinational company which comes here should be made to share the social burden of development. Why don't we insist that captive power plants must be part of every big project which comes? Let them put up their own captive power plants and produce electricity. We have power cuts in Bangalore for eight hours so that all those companies which have come have enough power to run their undertakings, to run their offices, to keep themselves going. I believe that houses for the workers of these companies must be provided by these companies. Let them invest in the infrastructure as also in the social sectors so that it is not that they get all the benefits and we pay the price. I want to know how much investment the foreign banks—the banking sector is opened up—are making in the country. What is their contribution? How much of that money is going into social investment in the country as our nationalised banks are doing? It is easy to condemn the nationalised banks and say that they are not efficient, they are not this and they are not that. But it is the nationalisation of banks which took credit and money to the common people in every part of the country. Today we want them to compete and produce results. What are the foreign banks contributing to this country's development? I would like to know. Yet, we want to open the insurance sector; we want to open the nuclear energy sector. You open up everything to them. What you are going to be left with are, probably, the Parliament House and the Rashtrapati Bhawan to call your own. I am, therefore, asking for a level-playing field for the Indian industry. The Indian industry has, right or wrong, borne the burden of development during the very crucial and difficult years of this country. They have built a base. Here I say that the public sector enterprises have contributed more than any other sector in this country to creating a base for our industrial development. At a time when there was no investment from the private sector, Pandit Nehru said, "these are the new temples of India", and they were created. There are units which are doing well. Instead of strengthening them, we say, disinvest them because those are the only shares which the people will buy. Those which are not so good are sent to the BIFR for a package. The BIFR is packed with bureaucrats who have no background of economics. They are retired bureaucrats who are not bothered whether the public sector survives or not. How many former Chairmen of public sector companies are there on the BIFR? How many people are there on the Board who understand

the economics of development? It is nothing but a rehabilitation Board for retired bureaucrats. The IAS officials—of course, I am coming to the Pay Commission Report—are experts on everything from groundwater to ocean development to nuclear energy. That is the tragedy. The moment a unit goes to the BIFR, banks stop releasing money. The Government says, "You manage on your own". Where do they go? What is happing to the public sector undertakings before the BIFR? Can they survive? Of course, as far as the ones which are sick are concerned, they say, "We are not giving you money; you close down and go home." This is the tragedy today. There are large areas of land. Let that land be sold. Let there be disinvestment. But let that money be pumped back into those undertakings and those which can survive, be modernised. Don't just let that money go to balance your Budget in Delhi. That is where the money is going to bridge the gap, your revenue gap and something else. Last year's figures are going to come up in the Budget. The big gap has been bridged by all these things. It is not used for reviving or rejuvenating the units whose land you are selling. I would like to say that the SCOPE has brought out a beautiful booklet on disinvestment policy and programmes I am sure you have got a copy of it. Please read it and see what they have to say about the people who really slogged for the public sector and what they have to say about the disinvestment policy. Madam, I come for a minute to the pay Commission Report. I know it is going to create a great deal of debate in this country. But no Pay Commission report has ever been as rejected, if I am say so, by all sections, as the present one. What have you got out of it? Except for one single Service, the rest have all been treated as second class Services. There is nothing to look forward to. If you are gong to pay somebody Rs. 26,000/-, Rs. 30,000/-, Rs. 40,000/- simply because they are underpaid, I would like first an analysis to be made by the Finance Ministry, not by the Department of Personnel on the total earnings of an officer of the rank of Joint Secretary or Director or Under Secretary. When an MP's salary is talked about, you talk about free housing, free water, free electricity, etc. Let it all be firmed up into a basket and see what each one gets. Then, to add insult to injury, while we are talking about reducing the overheads, what is the recommendation? That every officer above the rank of Director must have a telephone orderly to pick up his phones. As it is, without those orderlies, they don't come on the phone. And you give them telephone orderlies at home to pick up their phones? Are we going back to the British Raj? Are we going back to the Nawabas of Oudh? What are the talking about? In a socialist environment, they need orderlies at home to pick up their phones? All of them are walking around with phones in their pockets, the new status symbols which have come out-cellulars, cardless phones and so on—and yet they want orderlies at home.

Madam, the Pay Commission has set one Service against the other. It has created much discontent even between the lower sections and the so-called specialised higher sections of the Armed Forces.

AN HON. MEMBER: The Commission proposed a 30% reduction in the expenditure.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Let them reduce. you reduce the Government expenditure by 30%. It will do them good and they will work better. My point is, at whose cost is this being done? Which are the sections that are going to benefit from the Pay Commission's Report?

Madam, the Economic Survey has given the picture as it is. I am not much of an economist. but here are the actual indicators. you may say anything about us. You may call us anything you want. But these are independent survey figures. You take simply the question of GDP growth. We had reached 7.2% in 1994-

95. We came to 7.1% last year and it is provisionally estimated to be 6.8% Down. You take inflation. From 6% in 1992-93, we came down to 4% in between and we have now come to 8.7%. It says that is going to touch the double digit in the next few months. You take the question of agricultural production and this is where I want to emphasise. I say that the greatest tragedy is the slide-down in the agricultural production. It is predicted that despite the near normal monsoon in 1995, the foodgrains output of 185 MTs in 1995-96 was lower by over 6 MTs, as compared to 1994-95. This is the slide-down in the foodgrains production. It says that even in regard to wheat production. You have come down in wheat produciton by 3.2 MTs.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The year 1995-96 was the Congress year.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry. What I am saying is about the trends.

DR. BIPLAB DASGUPTA: In 1996-97, there has been an increase by 3 MTs. You are misleading the House by giving wrong figures. In 1995-96, wheat output declined and overall the decline in the foodgrains output was to the extent of 5 MTs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Dr. Biplab, let her have her say. If you have anything to say, say it when your turn comes. Don't interrupt her like this.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It is 3.2 MTs lower than the 1994-95 output of 65.8 MTs. It is less by 3.2 MTs. These figures are available in this paper. I will give it to you.

SHRI JIBON ROY: Madam...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Jibon Roy, sit down.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I will now come to industrial production. From 11.7% in 1995-96, it has come down to 9.8% in 1996-97. In every respect, whether it is foreign trade or some other sector, there is a downward trend when you compare it with either last year or with the provisional figures that are coming out for the coming year. It is, therefore, very clear.

Today, you are talking about dual pricing in the Public Distribution System. I am asking you: Why do you want dual pricing?

I would say, remove all those who don't deserve the PDS from the PDS list. Let those alone who deserve it have this benefit. Why should all of us be having the benefit of PDS? Why should Secretaries to Government and all those in this country who do not deserve this have the benefit of PDS? Let us pay the market prices. Let those who are below the poverty line, and those who do not pay income tax, have the benefit of PDS. But, if you say "No, we will do this", what will happen is, what you are giving at 50% for the poor will automatically go into the black market. The poor will not get it. Those who are there will pay higher prices and all that you supply for the so-called weaker sections will go into shops which will sell them at the market rate. So, all that you are going to do will add to the overheads and to the corruption which this is going to cause.

Madam, there are just two more points that I want to make. We are supposed to be celebrating fifty years of our freedom this month. There is a special mention of this by the President. There were so many programmes which were supposed to have been launched on the media. Now, you can challenge me again, but I have got this from very senior people in Doordarshan and Akashvani. Programmes were prepared but they were rejected. Do you know what was said? "Oh! there is too much of Congress projection in these programmes." What can you do if the Indian National Congress was in the lead of the Indian freedom movement? It wasn't the Congress (I) or somebody else. It was a

national movement. You may not have been there. Somebody else may not have been there. That is not the point. The point is, can you say that you cannot show a movement simply because it had leaders, who became leaders of the country, that belong to a particular party? They were freedom fighters. They were part of it. But all the programmes have been rejected and have not been allowed to go on the air. Yet, we are told that we are a distinguished supporting party. We are needed for voting. We are needed for getting you going. But when it comes to the freedom movement, you want to black out a chapter of Indian history forgetting that most of you, wherever you are sitting today in both the Houses, have had your basic grounding in the freedom movement or in the post-freedom movement era in the Congress. Therefore, I am saying that this kind of petty politics, when celebrating fifty years of freedom, is something which I just don't understand. Can't our minds, for at least this one particular event broaden out and cut across party lines? And then we are talking about big Bills—the Prasar Bharati, braodcasting, opening up, freedom of the waves and so on. When we have minds which are imprisoned and closed, what do we expect to release through the media? Therefore, I would say, today you have an exodus from the Doordarshan and the other media to private channels because you don't allow creativity. You don't allow people, who are professionals, to perform. You want the bureaucrats to sit and decide what is good, what is bad, what will happen and what will not happen. You down-grade posts in Doordarhsan when you are expanding. An Additional Secretary-level post becomes a Joint Secretary-level post to fit in individuals. Instead of raising the levels, knowing the impact of growing media challenge in this country, you are worried about individuals! You bring the post down and put lower level officers to run a big medium! What is happening? Do you have a perspective? Do you have an idea of what the mass media can do or undo for this country? Are you serious about projecting the national image, which must be done? I had even pleaded, let us have a joint celebration of the freedom struggle for SAARC. Get the countries together. We fought together at that time. Let us celebrate together the freedom of this sub-continent. We are not prepared. And, therefore, I would say that it doesn't help to divide ourselves on these petty lines.

Madam, the Foreign Minister is here and I wish, as I said before, to congratulate him on the many initiatives that he has taken. The latest agreement with Iran and Turkmenistan—there are so many of them now—I think, is a historic agreement. You have had the Ganga waters dispute sorted out with Bangladesh, which, I think, is another historic event for the sub-continent and for better public relations between neighbours. I would also say that we have to go further, particularly in the SAARC region, because with globalisation, the regional responses and creating an alternative market place within the SAARC region, because with globalisation, the regional responses and creating an alternative market place within the SAARC region where we can compete together with the outside world, are very necessary. Madam, we know what politics is. Ultimately, trade and economics are more important than political differences. When it comes to trade and economics, people forget a lot of other differences, provided they can make money together.

Madam, I want to point out something which I have never heard in national reports. I was reading an international report—I am bringing it to the notice of the Foreign Minister—which says, "India has consistently been one of the providers of soldiers since the U.N. Operations in Congo in 1960. The U.N. owes India more than 58 million dollars for peacekeeping operations, for which we have been sending soldiers. It is the

second largest third world country to which today the U.N. owes more than 58 million dollars." Madam, 58 million dollars is not a small amount. The largest defaulter on the peacekeeping front is the great champion of democracy, the United States, and yet we the third world countries are used for fighting battles for peacekeeping; whether it is in the Middle-East or anywhere else, we are sent. Our U.N. representative says, "We are not in the business of making money out of peacekeeping operations. We provide soldiers on U.N. salaries. That is why, there is no dearth of volunteers to serve in U.N. peacekeeping forces." It is not just a question of paying them. The question is : What are we doing to recover what is our due for these peacekeeping operations? The tax-payer pays to fight battles in international arenas for powershere and there, who want to keep the peace. A seat for us in the U.N. Security Council is denied, but when it comes to peacekeeping, when it comes to everything else, India has to be in the forefront, and we are treated as the only one who can provide peace.

Lastly, Madam, I being an M.P. from Karnataka, cannot close without briefly mentioning about Karnataka. We have a Janata Dal Government there. We have very recently gone through an election in Ramanagaram where, I hope, the Janata Dal has seen the writing on the well. All the three seats have been lost by the ruling party in my State. You have a Chief Minister who makes public statements which neither bring any credit to him nor to women nor to the State. What I want to point out here is that after Ramanagaram, the Chief Election Officer who put his foot down against any kind of booth-capturing and who had the courage to stand up to the pressure, has been shunted out within a week—sent on leave—and another man posted to his place. This is the freedom of Election Commission that we have all been talking about for so long. The CEO has been shunted out. Madam, I would also like to say that police officers and others also played their role—I am not mentioning about them—but, I would like to point out that there was a firing during that election on mill workers in which four people died. The CPM unions are very quiet now. In an earlier byelection, when one person had died, there was a march from there to Bangalore by the Janata Dal M.P. of the local area who is no less than our present hon. Prime Minister. It was a grand march against what they called police atrocities and firing. This time, four people have died, but there is not even a statement and there is no protest. What is this? It was...

SHRI M.A. BABY: I had protested.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You protested, But I am talking of the Government. We have been saying why are there dual standards? When four people have died this time, there has been no response.

Madam, these people talk so much about containing communal forces, the people who have been running the Government on the basis of keeping the BJP out-and we have been a party to it. I just want to say that one year ago, there was an election to the City Municipal Corporation in Ramanagaram. The Janata Dal has 14 seats, we have 11 and the BJP has seven. But the Janata Dal thought it proper to have an alliance with the BJP, gave the Vice-Presidentship to the BJP, took the Presidentship and kept the Congress out. And yet when we talk about fighting communal forces, we are told that we are hand in glove with communal forces, we are this and we are that. Today, you have this City Municipal Council in Ramanagaram constituted one year ago in which the BJP has the Vice-President, the Janata Dal has the President and the Congress sits in the opposition.

SHRI TRILOK NATH CHATURVEDI: We are the only nationalist party. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI MARGARET ALVA: Therefore, what I am saying is that we should not talk about an alliance of convenience. You have seen it and it is happening. You see the writing on the wall. You may treat us as untouchable when it suits you. But remember one thing and you cannot challenge me on this. There is no other party with the reach that the Congress has from the Burmese border in Mizoram to the Pakistan border in Kutch. There is no other party which has an office in every village and in every corner of this country. You might be great heroes in your local areas. But we have seen the ground realities. We may be out of office today. But I know this party has a future. We will fight back and rise again to prove to you people that ultimately we are the only national party. You may come; you may go; you may form alliances and fall apart. You are already falling apart in various places. We are prepared to be defeated; we are ready to pay the price when the people are angry with us. But, ultimately you will realise that we are the ones who stand for something. We have paid the price when there had been aberrations. But we have had the courage to fight and come back. Madam, I am not holding anything against anybody. But I want all my friends on that side to realise that ultimately if they are going to fight communal forces, if they are ready to build a country based on secular democracy, they cannot count the Congress out. Without us, they are all out. Thank you, Madam.

SHRI M.A. BABY: Madam, I want to say one thing in connection with what. ...(*Interruptions*)...

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, एक मिनट। मैं आपके जरिये से शंकरराव चौव्हाण जी तक यह बात पहुंचना चाहता हूं कि यह बुलबुल जो इस शाख पर बैठकर इतना चहक रही है वहां बिठाकर उसका गला क्यों घोंट रहा था?

†شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ ایک منٹ۔ میں آپکے ذریعے سے شنکرراؤ جوہان جی تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہ یہ بلبل جو اس شاخ پر بیٹھکر اتنا چہک رہی ہے وہاں بٹھاکر اسکا گلا کیوں گھوٹ رہا تھا۔]

SHRI M.A. BABY: Madam, Your colleague has made a very fine speech. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): She is a colleague of all of us. ...(*Interruptions*)...

SHRI M.A. BABY: Yes, Madam. ...(*Interruptions*)... Madam, with regard to the concluding part of her speech, I would like to say that she has really proved herself a courageous lady. To have such hopes about the future one requires so much of courage. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI MARGARET ALVA: You wait and see. ...(*Interruptions*)... I would like to see you after Jyoti Babu in Bengal. ...(*Interruptions*)...

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे पहली बार इस सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिला है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश असेंबली में लम्बी मुद्दत तक रहा हूं इसलिए वहां भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बार-बार बोलते-बोलते मेरे काले से सफेद बाल हो चुके हैं। लेकिन यहां आज सुनने पर ऐसा लगा कि बोलने वालों का एक खास दर्द था। अभी मार्ग्रेट आल्वा जी, जो अभी बोल रहीं थीं, उनका एक दर्द बोल रहा था कि सत्ता से हटे हैं कैसे सत्ता में आयें। एक 13 दिन सरकार वाले बोले हैं इस उम्मीद में कि शायद कभी 14 दिन की सरकार मिले और कुछ ऐसे लोग भी इस सदन में बैठे हैं जिनको हर वक्त यह खतरा रहता है कि यह सत्ता कब तक है। ऐसे माहौल में जाहिर है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, उसका मतलब

†[] Transliteration in Arabic Script.

और हमारी राय इन सब के बारे में कोई खुलकर कहने की हैसियत में नहीं है। मार्ग्रेट आल्वा जी ने जो मेरे से पहले की स्पीकर थीं, उन्होंने कांग्रेस के बारे में बड़े अच्छे सपने पूरे देश को दिखाए। यकीनन कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी। सन् 1942 में वह कांग्रेस जिसके बारे में यह कहा जाता है कि एक प्याले में लोग खाते थे और उन खाने वालों को किसी का धर्म मालूम नहीं होता था कि उनमें हिन्दू कौन था और मुसलमान कौन था। अंग्रेजों की साजिश से तैयार की गई गोली जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, उनको लेने के लिए फौजी इंकार कर देते थे कि हम अपना धर्म, अपना ईमान खराब नहीं करेंगे। उस समय ऐसा हिन्दुस्तान था और उस समय यकीनन ऐसी कांग्रेस थी जिसमें मौ॰ अली जिन्ना भी थे, लियाकतअली खां भी थे, सुभाषचन्द्र बोस भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। लेकिन इस पर बहरहाल सोचना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को कि वह कौन से हालात हुए जिनसे इन लोगों को एक ऐसा फैसले पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जो फैसला हिन्दुस्तान की तकसीम का सबब बना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हमने बहुत बड़ा स्टेट्यु यहां पर लगा रखा है। सौ-दो सौ इन्सानों को मिला कर उनके जिस्मों से अगर बनाया जाए तो नेहरू जी का जिस्म नहीं बनेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिस्म नहीं बनेगा जितना बड़ा जिस्म यहां खड़ा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मुल्क में सेकुलरिज्म की ऐसी पहचान थे जैसी पहचान 50 वर्षों तक दूसरी पैदा नहीं हो सकी। उनके साथ यह बड़ी बदकिस्मती रही इस मुल्क में रहने वाले अकसरियत धर्म को मानने वाले लोग भी उन्हें सेकुलर नहीं मान सके। मैं उसका सबूत भी दूंगा। खुद मुसलमानों ने भी उन्हें अपनी कौम का गद्दार कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1952 में पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़ा था। जिस सेकुलर कांग्रेस की दुहाई आपने दी है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टू नेशन थियोरी के खिलाफ थे, वह नेशन थियोरी में यकीन रखते थे और मुसलमानों के हाथों से उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गले में जूतों का हार डलवाया था वही सेकुलर कांग्रेस जिसके लिए अभी आपने फरमाया है 1952 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इतने बड़े हिन्दुस्तान में जिसकी सरहदें अभी आपने बताई हैं कहां से कहां तक हैं उस हिन्दुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युएंसी ऐसी नहीं मिली जिसके बारे में यह कहा जा सकता कि यह कांग्रेस के सेकुलरिज्म के सोच की निशानी है। उन्हें रामपुर से इलेक्शन लड़ाया गया जहां मुसलमानों की भारी अकसरियत है। यह था आपकी कांग्रेस का सेकुलरिज्म। आपकी कांग्रेस का सेकुलरिज्म, इस सदन में बैठे हैं 6 दिसम्बर को मस्जिद गिर गई उस वक्त तो आप कुछ नहीं कह सके, उस वक्त प्रधानमंत्री पर अंगुली नहीं उठा सके, उस वक्त आप पूरे देश के सामने यह नहीं बता सके कि आप इस देश के गृह मंत्री भी हैं और जब आपका साथी कमज़ोर हो गया, वह ठगी में पकड़ा गया और वह अदालत में मुजरिम बन गया, कैसी दोस्ती आपने निभाई?

दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की
लोगों ने मेरे सेहन में रास्ते बना लिये।

आपने उस वक्त उसकी पीठ में खंजर घोंपा। दोस्ती का तकाज़ा यह था कि जो कल तक हमारे साथ था, आज हम उसके साथ होते। अगर आपके अन्दर वाकई कोई मोरल करेज था, आप इस देश के गृह मंत्री थे, गृह मंत्री का बहुत बड़ा दर्ज होता है, देश के माथे पर कलंक लग रहा था, मस्जिद टूट रही थी और आप एक लफ्ज़ भी इसलिए नहीं कह सके कि आपको कुछ और दिन गृह मंत्री रहना था। जहां अखलाकी कदरें यह हों, जहां व्यक्ति का चरित्र यह हो, जहां देश के गृह मंत्री का चरित्र यह हो, जो पूरे राष्ट्र के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनियां की इन्सानियत के साथ धोखा कर सकता हो, उसका भविष्य क्या होगा, उस देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या चर्चा होगी? क्या कहा जा सकता है, क्या भला होगा गरीबों का, कहां इन्सानियत जिन्दा रहेगी, कहां सेकुलरिज्म आएगा, कहां कम्युनलिज्म खत्म होगा, इन्सान से इन्सान का टकराव कैसे नहीं होगा, सूरत की सड़कों पर 14-14 साल की बच्चियों को नंगा करके कांच पर नचाया जाएगा? वह कांग्रेस कोई और होगी, आज की कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं है। आज तो यह नहीं पता चलता कि कितनी कांग्रेस हैं। तिवारी जी की कांग्रेस है, इन्दिरा जी की कांग्रेस है, राव साहब की कांग्रेस है। आज कांग्रेस तो एक लौंडी बन कर रह गई है जिसको अपना कोई घर नज़र नहीं आता। इसलिए वह बात न करें। बात करें किसी ऐसे माहोल की जिसमें यह मुल्क अपने आप आगे ले कर चल सकें। बात करें हम किसान की, बात करें हम मजदूर की, बात करें हम बेरोज़गारों की, बात करें हम करप्शन हटाने की, बात करें हम हिन्दुस्तान की सरहदों पर फैली हुई बदअमनी की। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जहां बैठता हूं मेरे बाएं ऐसा व्यक्ति बैठे जिसके बैठने से मुझे अच्छा लगे, मेरे दायें ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे टीज़ न करे, सताए नहीं और पीछे से ऐसी आवाज़ न आए जो मेरा दिल दुखाने का सबब बने। हमारी

सरहदों पर यकीनन ऐसा माहोल होना चाहिए। उस माहोल को बनाने की कोशिश की जाए। मैं मुसलमान हूं अगर पाकिस्तान यहां हिन्दुस्तान की जमीन के किसी हिस्से पर बम फैंकता है तो मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि बम रामपुर की बस्ती पर भी गिर सकता है जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद पर गिर सकता है और आगरा के ताजमहल पर भी गिर सकता है। इसलिए मेरी ज़ाती ज़रूरत है, ज़ाती ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की जंग न हो। अगर कोई पाकिस्तान में रहने वाला हिन्दू यह चाहे कि हिन्दुस्तान से उसकी जंग न हो तो यह उसका फितरी फेल है, उसकी ज़रूरत है। इन ज़रूरतों को समझना और कहना, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस देश में यकीनन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि अगर हम चाहें कि हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते इस्तवार हों, अच्छे हों तो फिर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। उस सवालिया निशान का जवाब सरकारें दें। अगर किसी भीड़ में कोई शख्स एक पत्थर लेकर खड़ा हो जाए और भीड़ की तरफ इशारा करे, भीड़ भाग खड़ी होगी। कोई दीवार से टकराएगा, कोई गाड़ी से टकराएगा, कोई जख्मी होगा, किसी की हड्डी टूटेगी और हो सकता है कि कोई मर भी जाए। गलती पत्थर उठाने वाले की उतनी नहीं है जितनी गलती उस प्रशासनिक तंत्र की है जो खामोश खड़ा हुआ है एक तमाशाई की तरह और उस पत्थर उठाने वाले को देखता रहता है। उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि पत्थर उठाने वाले का हाथ या तो उसके जिस्म से अलग कर दे या उस हाथ को तोड़ने का काम करे। जब सरकारें कमजोर होंगी जब सरकारों के अंदर का अपना विश्वास कमजोर होगा, देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है और इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए। जमाना गुजर गया है कि इस देश को मजबूत सरकार नहीं मिली और यही वजह है कि आज वे लोग जो खुद चोर हैं जो खुद बेइमान हैं वे बेइमानों का हिसाब लेने पर उतरे हैं। यकीनन जितने राजनेता हैं सब चोर हैं, सब बेइमान हैं। उन बेइमानों में मैं भी हूं। मेरे गिरेबान पर हर किसी को हाथ डालने का हक है। लेकिन आज कितना अच्छा होता कि हम कुछ तो ऐसे होते कि हमारे पर एक डाक्टर, इंजीनियर, इन्कम टैक्स आफिसर, सेल्स टैक्स आफिसर और इन्साफ की बड़ी-बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए दूध के नहाए हुए लोग हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हिन्दुस्तान की सियासत की कुर्सी पर सबसे बड़ा बैठा हुआ व्यक्ति अपने पद से हटने से 15 रोज पहले विज्ञान भवन में घुसता है, उसके दाखिल होते ही विज्ञान भवन के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इस देश के इन्साफ की कुर्सी पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज भी खड़े हो जाते हैं—ऐसा होना भी चाहिए, हिन्दुस्तान का बादशाह दाखिल हो और कोई खड़ा न हो यह भारत वर्ष की और हमारे मादरे वतन की तौहीन होगी—पूरा मुल्क खड़ा हो गया लेकिन वही देश का प्रधान मंत्री 15 दिन बाद ठगी का मुजरिम हो गया तो हिन्दुस्तान में रहने वाले 90 करोड़ इन्सानों का सिर पूरी दुनिया के सामने झुक गया। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा लज्जा की बात कोई नहीं हो सकती कि देश का प्रधान मंत्री ऐसा हो। किसी भले आदमी को आप रास्ता रोककर कहें कि तुम ठग हो तो वह आपको चिपट जाएगा, मारने लगेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि मुझे ठग कहते हो। इस देश का बहुत बड़ा नेता जो रामराज्य लाना चाहता हो पूरे देश को खाक और खून में नहलाने का काम करे! इस देश का सबसे बड़ा रामराज्य का दावेदार हवाला कांड में मुजरिम बन जाए, बेइमानी में पकड़ा जाए और पूरी दुनिया उसे बेइमान के नाम से जाने! उसने लूटा हो पैसा उन कर्मचारियों का, मेहनतकशों का, मजदूरों का जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, रहने को मकान नहीं मिलता! कैसे करेगा देश तरक्की। लेकिन जब कुदरत का इन्साफ होता है तो वही देश की गद्दी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा व्यक्ति—जो विज्ञान भवन में घुसता था सब खड़े हो जाते थे—जब दिल्ली की अदालत के एक छोटे से कमरे में दाखिल होता है और एक छोटा सा मैजिस्ट्रेट खड़ा होता है तो वह खड़ा हो जाता है, वह बैठता है तो वह बैठ जाता है। हमें इन चीजों से सबक लेना चाहिए। कहीं हो कोई, चाहे सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हों या सत्ता से हटे हुए लोग हों या सत्ता में आने का सपना देखने वाले लोग हों उन्हें सोचना पड़ेगा इस देश में रहने वाले उन इन्सानों की तरफ जिन्हें बिजली नहीं मिलती, जिन्हें बिजली के नाम पर झूठे वादे मिलते हैं। मैं ऐतराज नहीं करता। मेरी हैसियत भी नहीं है ऐतराज करने की। लेकिन देश का प्रधान मंत्री घोषणाएं करे और उन घोषणाओं में से एक घोषणा भी पूरी न हो। नहीं करनी चाहिए ऐसी घोषणाएं। कोई मतलब नहीं है ऐसी घोषणाओं का। तालियां बजवाने से, नारे लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे आस्था हटती है जनतंत्र से, लोकतंत्र से उन लोगों की जो वोट देते हैं। हमें सबक लेना चाहिए इससे हमारे मुल्क की आजादी को 50 वर्ष हो गए। यकीनन हमें इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन इन 50 वर्षों में हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि वोट देने वाले लोगों की फीसद घटती चली जा रही है।

इसका क्या मतलब हुआ। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कहने को तो एब्सालूट मेजारिटी मिली है पाकिस्तान में प्रधान मंत्री को लेकिन क्या वह एब्सालूट मेजारिटी ऐसी है जिसकी बुनियाद पर वहां के देश को चलाने वाला यह कह सके कि इस मुल्क की अक्सरियत मुझे हासिल है। 35 फीसदी लोगों का मिला हुआ वोट जिसमें कुछ फीसद दूसरों की भी है, वह अपने आपको उस देश की तकदीर को बदलने वाला नहीं कह सकता। यह तभी हो सकता है जब हम गरीबों के दिल में जगह पैदा करें और गरीब जनता से किए हुए वादों को पूरा करें। बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। महंगा बीज मिलता है, महंगी खाद मिलती है और जब किसान को यह सब महंगा मिलता है—और सस्ता बेचते हैं, महंगा खरीदते हैं, कपड़ा महंगा लेगा, बच्चे की पढ़ाई महंगी होगी—हमारे यहां एक रिवाज बन गया है, 'यह सदन हो या...। या ऐसा ही एक गोल सदन इस के बराबर का हो, एक फैशन-सा बन गया है—गरीबी से लड़ा जाएगा, महंगाई कम की जाएगी। महोदया, महंगाई कम करने के लिए यकीनन हमारे देश के खाद्य मंत्री ने एक नयी स्कीम चलानी चाही है सस्ता अनाज देने की। मैं इस से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि "आउटराइटली" बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए कि इस का कोई मतलब नहीं है। इस से कोई फायदा नहीं होगा। यह एक ऐसी स्कीम है जिसे एक दर्दमंद दिल रखनेवाला इंसान ही दे सकता था। ऐसा नहीं है कि इस का कोई फायदा नहीं होगा। यकीनन इस का फायदा होगा और इस का फायदा पहुंचते हुए हम ने अपनी आंखों से देखा है। ट्रकों में लदे हुए अनाज की बोरियों को हम ने गरीबों में बंटते हुए देखा है। यह यकीनन हो सकता है कि उस का सौ फीसद फायदा गरीब को न पहुंचे, लेकिन सौ फीसद फायदा नहीं पहुंचेगा, जीरो फीसद होगा और नुकसान होगा, यह कहना सही नहीं है।

हमें एक बात और भी सोचनी होगी कि महंगाई पर हमारा कब्जा हो, कंट्रोल हो तो क्या सिर्फ गेहूं सस्ता कर देने से महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा? चावल सस्ता कर देने से महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा? हमें यह भी देखना होगा कि गेहूं खाने वाला व्यक्ति पहनता क्या है? उस के पैर में जूते किस चीज के होते हैं? उस का बाप जिंदा है या नहीं? क्या वह बीमार है? उस की मां जिंदा है या नहीं या वह बीमार है? उस की मां मर गयी है तो उसे कफन चाहिए उसे शमशान में जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। उसे दफन करने के लिए पटरे चाहिए, कपड़ा चाहिए उस की कब्र को खोदने वाला एक मजदूर चाहिए। महोदया, यह एक बहुत लंबी जिंदगी का प्रोसेस है जोकि पैदा होने से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक है। वह सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं है, कपड़ा भी है। वह चश्मा भी है जो वह अपनी नजर पर लगाता है। उस के बच्चे के जूते हैं, स्कूल की फीस है, उस की किताबें हैं, दवाइयां हैं और न जाने जिंदगी की कितनी खुशियां और गम हैं जो कि महंगाई के साथ जुड़ी हुई हैं। उस की तरफ हमारी निगाह नहीं जाती।

महोदया, उत्तर प्रदेश इस देश का दिल है। वह बहुत बड़ा प्रदेश है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में रहनेवाले कि उत्तर प्रदेश देश का सब से बड़ा राज्य है। पाकिस्तान से बड़ी उस की आबादी है और न जाने कितने दुनिया के मुमालिक हैं जिन से बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्या हमें आज यह सोचने का भी वक्त नहीं है कि वहां के राज्यपाल ने गरीबों के साथ अभी चंद दिन पहले क्या किया है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सदन सक्षम है फैसला करने के लिए, बराबर का सदन सक्षम है फैसला करने के लिए कि राज्यपाल चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है। राज्यपाल जनता के एहसास का हिस्सा होता है और अगर राज्यपाल कोई गलत काम करता है तो उस की पूरी परछाई केन्द्र सरकार पर पड़ती है और केन्द्र के मुखिया पर लोगों की उंगली उठती है। महोदया, अभी चंद रोज पहले एक तुगलकशाही हुक्म जारी हुआ है। महोदया, अब कौन जाता है सरकारी अस्पताल? डाक्टर का बेटा नहीं जाता, इंजीनियर का बेटा नहीं जाता और यहां तक कि क्लर्क और चपरासी का बेटा भी अस्पताल नहीं जाता है। अस्पताल जाता है कपड़ा मिल में काम करने वाला मजदूर, सूत के रेशे से जिसे टी०बी० हो जाती है। अस्पताल जाता है बीड़ी बनाने वाला मजदूर, निकोटिन की खुशबू से जिसे कैंसर हो जाता है, टी०बी० हो जाती है। वहां जाता है रिक्शा चलानेवाला, जिस के फेफड़े नहीं रहते रिक्शा चलाते-चलाते। वहां जाता है पत्थर तोड़नेवाला, झल्ली ढोनेवाला जिस के फटे हुए कपड़े होते हैं और जिस्म से बदबू आती है। ऐसे लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो फिर हमारे शहरों और हमारी बस्तियों में बने हुए प्राइवेट क्लीनिक उस का सबूत नहीं दिया करते। लेकिन वह अस्पताल है जहां एक रुपया फीस देते हुए भी कमर दोहरी हो जाती है गरीब की। जहां एक्सरे के दस रुपए देने की हिम्मत न हो गरीब की वहां उस की फीस को तीन गुना/चार गुना कर दिया जाता है। जहां फ्री दाखिला हो, वहां फीस कर दी जाए। टी०बी० के मरीज को बलगम की जांच कराने के लिए 30 रुपए देने पड़े।

अपने खून की जांच कराने के लिए पैसे देने पड़े। तो यह कोई इंसाफ नहीं है। महोदया, इन सवालों पर भी अगर हम गौर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमारी नजर पूरी तरह नहीं जाएगी।

महोदया, बड़ी फिक्र होती है कि हमारे देश में जगहें बढ़ते हैं। आज हमारा नौजवान जो फिल्में देख रहा है वह भी इस के लिए एक कारण है। हमारे मंत्री जी यहां नहीं है जिन का विभाग है उड़ने का, घूमने का और रंगरेलियों का, वह यहां तशरीफ नहीं रखते हैं। वैसे भी नहीं रखते है। जिस तरह के प्रोग्राम हम टेलीविजन पर देते हैं, क्या उससे हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे, क्या उससे हम अच्छे कल का सपना देख पाएंगे, क्या हम अपनी बच्चियों और बच्चों को एक अच्छा हिन्दुस्तान दे पाएंगे? टेलीविजन पर आने वाली फिल्में और प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें बैंकों को लूटने के तरीके, किस तरह रैप किया जाए या किस तरह कत्ल किया जाए और मुजरिम न पकड़ा जाए, इस तरह के प्रोग्राम हैं। इनके बजाय हम इन चीजों को बदलने वाले कुछ प्रोग्राम दें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे नौजवान डिग्रियां लेने के बाद नौकरी नहीं पाता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि कोई भी सरकार सारे डिग्री हासिल करने वाले लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन सरकारों के पास ऐसे प्रोग्राम होने चाहिएं, जिससे अनएम्पलायड यूथ को काम मिल सके, बैंकों से उसे कर्जे मिल सकें, ऐसी स्कीम हो जिससे उन्हें पैसा मिल सके। होता वही है, जैसे अभी चर्चा चल रही थी हवाला में पकड़े जाने वालों की, ठगी में पकड़े जाने वालों की। हमारे यहां यूरिया स्कैण्डल एक ऐसा स्कैण्डल है, जिनके बारे में कई विदेशी मैगजीनों में भी पढ़ने को मिला। वे लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किस्से कहानियों में भी नहीं सुना था कि जिसका कोई दफ्तर न हो, जिसका कोई ट्रक न हो, जिसका कोई कागज न हो, लाखों टन यूरिया मुल्क में आए और उसका इस्तेमाल भी हो जाए। ऐसे जिस देश में स्कैण्डल होते हों, उसका क्या कहना। जहां करोड़ों रुपया, दस, बीस, तीस करोड़ रुपया किसी शख्स के बिस्तर पर बिछा हो, मैंने तो हंस कर कहा था कि जब एक मंत्री जी के घर से इतना पैसा निकले, अगर उन्हें मेरा नाम याद होता तो मेरा नाम ले लेते, मैं उससे इंकार नहीं करता क्योंकि हद से हद यही तो होता कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझसे इन्कम टैक्स उसका 40/50/60 परसेंट, जितना चाहते ले लेते, लेकिन बाकी पैसा तो मेरे लिए बच जाता। जहां देश के मंत्री इतनी बड़ी रकम के बारे में यह कहें कि यह रकम मेरी नहीं है, वह देश नंगों का नहीं हो सकता, वह देश गरीबों का नहीं हो सकता, वह देश भूखों का नहीं हो सकता, वह देश लुटेरों का देश हो सकता है। उस देश में कुछ लुटेरों ने इस सोने की चिड़िया को बिल्कुल एक ऐसी पीतल की चिड़िया बना दिया है, जिस पर आप कितना ही ब्रास या पालिश लगाइए, उस पर चमक आने वाली नहीं है।

महोदया, पंजाब के चुनाव हुए। यह जाहिर है कि पंजाब हमारे देश का एक ऐसा सूबा है, जो खुशहाल है। इसी सूबे से बिगड़े हुए हालात का रिफलेक्शन जब पूरे मुल्क में हुआ था और मेनका गांधी जब पीलीभीत से चुनाव लड़ी थीं तो नफरत फैलाने वाले लोगों ने एक नारा दिया था, जिस तरह कभी हमारे बहुत अच्छे साथी, बी०जे०पी० के लोगों ने कुछ नारे दिए थे, उसी तरह एक नारा पीलीभीत में लगा था—"बेटी एक सरदार की, देश के गद्दार की"। नारों के लिए यह देश हमेशा मशहूर रहा है। कुछ सोशलिस्टों ने भी बड़े अच्छे अच्छे नारे दिए—"संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाएं सौ में साठ"। नारों का तो यह देश रहा है। "बच्चा बच्चा राम का, कुर्बानी के काम का", "राम का बदला लेना है, बाबर की औलादों से"। अब मैं नाम नहीं लेता, आपोजीशन के लीडर साहब हमारे बुजुर्ग है, आप जब उर्दू बोलते है तो सच कहता हूं कुछ लोगों के मुंह से उर्दू बोलते सुनकर अच्छा लगता है। एक बार जाकिर साहब से तालीमे-इस्लामी के जमाने में मिलने का मौका हुआ। जब मैंने उन्हें बोलते हुए सुना तो ऐसा लगता था कि उनके मुंह से अलफाज नहीं, फूल झड़ते हों। यकीनन आप जब उर्दू बोलते है तो लगता है कि कोई उर्दू बोल रहे है, लेकिन जब आपके जेहन पढ़ते है तो फिर आप ही के जेहन पर अफसोस नहीं होता बल्कि अपनी तकदीर पर भी अफसोस होता है। नाम आपका हमारे लिए किस कदर खुशबख्त है और हमारी बदबख्ती यह है कि बाबरी मस्जिद, जो कि एक धक्का है, आप उसे कुछ कहिए, आप उसके बारे में कोई राये न रखें, लेकिन आज की तारीख 4 बजकर 17 मिनट पर उत्तर प्रदेश सरकार का एफिडेविट हिन्दुस्तान की अदालत में है कि 22/23 दिसंबर, 1949 की रात कुछ शरपसंदों ने सीढ़ी लगाकर मस्जिद में दाखिला लिया, मूर्तियां स्थापित कर दीं और मस्जिद को नापाक कर दिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का खत है, उस जमाने के गृहमंत्री जी का खत है कलेक्टर के नाम, कि यहां से मूर्तियां निकाली जाएं, इसे मस्जिद की शक्ल दी जाए, नमाज कायम की जाए क्योंकि हम दुनियां को मुंह दिखाने की हैसियत में नहीं हैं। यहां मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, यह कोई जज्बाती बात नहीं है। मेरे लिए यह मामला आस्था का हो सकता है या नहीं हो सकता है लेकिन यह सदन

क्योंकि उसूर से बनाया हुआ सदन है, इसलिए मैं समझता हूं कि यहां न तो कोई मुसलमानों से, न हिन्दुओं से, न सिख-ईसाइयों से, धर्म से ताल्लुक रखने वाला कोई निशान, कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन मैं उन्हें, जो इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में मज़हबी इबादतगाहों को अपनी आस्था के नाम पर गिरा देना चाहते हैं, यह बता देना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा उनकी निगाह में धर्म का हो सकता है, आस्था का हो सकता है लेकिन मेरी निगाह में यह मामला आज की तारीख में इस वक्त हाई कोर्ट में लगे हुए उस हलफनामे के लिए है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगा रखा है कि यह मस्जिद है। इसलिए हम इसे कानून का मुल्क मानते हैं। अभी शास्त्री जी, जो यहां के एक बहुत ही सुलझे हुए, शरीफ और बड़े ही अच्छे व्यक्तियों में से हैं, बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। जब आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने संविधान की बात की तो मुझे संविधान के आपके इस जुमले में आपका पूरा व्यक्तित्व 6 दिसम्बर की तारीख सा कैलेंडर पर लटका हुआ नज़र आया। उस दिन जब संविधान की धज्जियां उड़ रही थीं, आपके उस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की रखवाली करेंगे, सुरक्षा परिषद में भी आपने यही वादा किया था, लेकिन इन सारे वादों की जब आपने.. (व्यवधान)..

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैडम मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मेरा नाम लिया गया है, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नाम लेने से कुछ नहीं होता है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं. (व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठिए। कृपया शांत रहिए।

श्री सिकन्दर बख्त: आप सब लोग, मेहरबानी से, न बोलिए, मैंने उनसे दरख्वास्त की है बैठने के लिए। हम बहुत सब्र के साथ सुन रहे हैं अपने अज़ीज़ को।

†اشفری سکندر بخت: آپ سب لوگ
مہربانی کرکے نہ بولئے۔ میں نے ان سے درخواست
کی ہے بیٹھنے کیلئے۔ ہم بہت صبر کے ساتھ
سن رہے ہیں اپنے عزیز کو۔

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैंने यह बात इसलिए कहीं कि शास्त्री जी ने धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष की बात कही है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष लफ्ज लिखा जाए या पंथनिरपेक्ष लफ्ज लिखा जाए, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आपको धर्मनिरपेक्ष पर आपत्ति क्यों हुई? उसमें हमें आपके ज़हन, आपकी सोच पढ़ने का मौका मिला। ऐसा लगा कि आप दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं और हैरत इस बात पर हुई कि हमारे बख्त साहब, जो कि अपोज़ीशन के लीडर भी हैं यहां, उन्हें खुद ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुबूल नहीं करनी चाहिए थीं। मैंने बात को कुसदन वक्फ के नाम से शुरू की और वह इसलिए कि कुरान, जो कि मुसलमानों के लिए आसमानी किताब है और वे उसके एक-एक लफ्ज को सच्चा मानते हैं। कुरान ने यह बताया है कि वक्फ क्या है और अल्लाह ने यूं कहा है कि ये चीजें, जो वक्फ हैं, उनका मालिक मैं हूं और जिन चीजों का मालिक अल्लाह हो जाए, उनके बारे में सुधार की बात करने वाला भी अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए। हैरत है, सिकन्दर बख्त साहब, वक्फ की जायदादों पर बनी कमेटी के आप चेयरमैन हैं। आपको कहां से, अखलाकी तौर पर भी यह हक नहीं कि आप और आपकी पार्टी, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली हो, सूरत की सड़कों पर बहन-बेटियों को नंगा करके नचवाने वाली हो, इंसानों का कत्लेआम करने वाली हो, उनके घरों को जलाने वाली हो, आप, जो मस्जिदों को गिराने में यकीन रखते हों, मस्जिदों को गिराकर आप यह समझते हैं कि आपने पार्टी के साथ बहुत बड़ी वफादारी का काम किया है, आप अगर सदन की बनाई हुई कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं तो इससे ज्यादा अफसोस की और निन्दा की बात दूसरी और क्या हो सकती है।

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन ज़ातियात पर उतरना कुछ

†[] Transliteration in Arabic Script.

हद से ज्यादा गुज़र गया है। अब हम कहां तक सब्र करें, कहां तक बर्दाशत करें? मेरा कहना यह है कि जिस किसी मौजू को सामने रखकर हमारे मोहतरम भाई बोल रहे हैं, बोलें, लेकिन ज़ातियात पर हद से ज्यादा उतरनी, सही नहीं है। कहां तक उतरना चाहते हैं? वह क़ाबलियत का सबूत दे रहे हैं या वाक़फियत का सबूत दे रहे हैं? जिस मौजू पर, जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, उसी पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है।

†اشفری سکندر بخت: صدر صاحبہ دخل دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ذاتیات پر اترنا کچھ حد سے زیادہ گزر گیا ہے - اب ہم کہاں تک صبر کریں - کہاں تک برداشت کریں - میرا کہنا یہ ہے کہ جب کسی موضوع کو سامنے رکھکر ہمارے محترم بھائی بول رہے ہیں - بولیں - لیکن ذاتیات پر حد سے زیادہ اترنا صحیح نہیں ہے - کہاں تک اترنا چاہتے ہیں - وہ قابلیت کا ثبوت دے رہے ہیں یا واقفیت کا ثبوت دے رہے ہیں - جس موضوع پر جس وشے پر آپ بول رہے ہیں اسی پر بولیں تو زیادہ اچھا ہے -]

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): मैडम, मैं एक प्वाइंट फार इन्फार्मेशन कह रहा हूं कि जो कमेटी बनती है सदन की और उसके जो चेयरमैन बनते हैं, उसको हमारे चेयरमैन साहब नॉमिनेट करते हैं, इसलिए उसको अगर हम हाऊस में चर्चा का विषय न बनाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

†اشفری محمد سلیم: میڈم میں ایک پوائنٹ فار انفارمیشن کہہ رہا ہوں - کہ جو کمیٹی بنتی ہے سدن کی اور اسکے جو چیئرمین بنتے ہیں - اسکو ہمارے چیئرمین صاحب نامینیٹ کرتے ہیں - اسلئے اسکو اگر ہم ھاؤس میں چرچا کا وشے نہ بنائیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا -]

श्री सिकन्दर बख्त: ज़ातियात पर उतरने का कोई मतलब नहीं है। कहां तक उतरना चाहते हैं? हम बहुत खामोशी से बैठे हैं।..**(व्यवधान)**..

†اشفری سکندر بخت: ذاتیات پر اترنے کا کوئی مطلب نہیں ہے - کہاں تک اترنا چاہتے ہیں - ہم بہت خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ "مداخلت"]

श्री मोहम्मद आज़म खान: सलीम साहब, मैं यहां नया ज़रूर हूं, मैं इस मैदान में बहुत पुराना हूं, आपकी उम्र से ज्यादा का हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आज़म साहब, इस सदन की एक परंपरा है। समितियां इस सदन के चेयरमैन बनाते हैं, इसके बारे में आप कोई जिक्र न करें तो अच्छा है। आप अपनी बात कहें लेकिन उसका जिक्र न करें...**(व्यवधान)**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: फिर तो आपको इतिहास दोहराना पड़ेगा...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप बैठ जाइए। आज़म साहब, आपके दल के पास 28 मिनट का समय है। आपने 3 बजकर 58 मिनट पर बोलना शुरू किया था, अब आपका समय बहुत कम रह गया है। इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कहें। अब आप अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें। आपका एक मिनट का समय और बचा है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरी मंशा किसी के ज़ाती ज़ज़बात को दुखाने की नहीं थी और न है। हम तो खुद ऐसे दुःखी लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले यह सोचा था कि मालूम नहीं अब हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ करोड़ लोगों को इस मुल्क में रहने दिया जाएगा या नहीं। लेकिन जब अंधेरा होता है और घुप्प अंधेरा होता है और मायूसी हर तरफ छा जाती है, कहीं से अगर कोई किरण नज़र आती है तो वह किरण करीब से नहीं, बहुत दूर अंधेरे से भी नज़र आ जाती है। इस मुल्क में फैले हुए अंधेरे में हमें कुछ किरण नज़र

†[] Transliteration in Arabic Script.

आई और जम्हूरियत, इंसानियत, सेक्युलरिज्म, इंसानी रिश्तों में यकीन रखने वाले कुछ लोग खड़े हुए, जिनका धर्म इस्लाम नहीं था, वे हिंदू थे और उन्होंने कोशिश की कि इस मुल्क को बचाया जाए। इस मुल्क में रहने वाला कोई शख्स अब न तो सरहदों के बाहर फेंका जा सकता है, न किसी के लिए पनाह समुंदर हो सकता है या आग हो सकती है और न ही आज के इस युग में यह नारा फलीभूत हो सकता है कि "तुम्हारा पाकिस्तान या कब्रिस्तान"।

इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी मायूसी से मेरा दिल दुख सकता था लेकिन हम तो इतने मायूस रहे हैं कि हम उस मायूसी की सरहदों को पार कर चुके हैं। अगर आपको उस दर्द का अहसास होता, आपने उन तकलीफों को देखा होता, उन लुटती हुई अस्मतों को देखा होता और उन बरबाद खानदानों तक आपकी पहुंच होती जिनमें किसी की मां नहीं रही, किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का शौहर नहीं रहा, किसी का बाप नहीं रहा,तो यकीनन आप यह नहीं कह सकते थे। जब 6 दिसंबर को साढ़े तीन सौ मकानात नज़रे-आतिश किए गए, जलाए गए तो एक साध्वी जी ने कहा कि रोशनी हो गई। मकानों को जलाकर अंधेरे की तरफ से रोशनी का आदेश हुआ। एक डेढ़ बरस का बच्चा जलते हुए मकान से घुटनों के बल बाहर निकला...(**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र मोहन: मैडम, क्या यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात हो रही है? मेरा प्वाइंट आॅफ आॅर्डर है...(**व्यवधान**)

Madam, I am on a point of order. Point of order. Point of order...(*Interruptions*)... श्री लक्खीराम अग्रवाल: महोदया,*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप लोग बैठ जाइए ...(**व्यवधान**) आप मेहरबानी करके बैठ जाइए...(**व्यवधान**) Nothing is going on record.

SHRI NARENDRA MOHAN: Madam, I have the right to raise a point of order...(*Interruption*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): No point of order. बैठ जाइए, बैठ जाएं ईश दत्त जी।....(**व्यवधान**)

काइंडली टेक योर सीट।....(**व्यवधान**) विरोधी दल के नेता खड़े हैं, आप बैठिए।....(**व्यवधान**) आप लोग तो बैठिए, बैठिए-बैठिए। मोहम्मद सलीम, टेक योर सीट।

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राष्ट्रपति के एड्रेस पर वोट आफ थैंक्स पर बहस है और यह भी हो सकता है कि उसमें अयोध्या का जिक्र आए। लेकिन जिक्र आए उसके बाद तकरीर दूसरी मौजूओं तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद हम लौटकर वहीं आ जाएं और सिवाए इशतियाल अंग्रेजी के और कुछ नहीं है। क्या दुरूस्त है। उसको भी तो रोकिए। यह लोग तो बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं, हम भी खामोश बैठे हुए हैं। मैंने अपने एक अज़ीज साथी का इरादतन बिठा लिया कि अच्छा है दिल का भड़ास निकल जाए। लेकिन कहां तक जाना है इसको। आखिर कहीं तो रुकना चाहिए। हम लोग बहुत बर्दास्त से बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत इज्जत के साथ और एतराम के साथ सुन रहे हैं। लेकिन इसकी इंतहा क्या होनी है, यह तो हमको बतला दीजिए। हद हो गई है।

†[] شری سکندر بخت: صدر صاحبہ - میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں - کہ راشٹرپتی کے ایڈریس پر ووٹ آف تھینکس پر بحث ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایودھیا کا ذکر آئے - لیکن ذکر آئے اسکے بعد تقریر دوسرے موضوع تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد ہم لوٹ کر وہیں آجائیں اور سوائے اشتوال ایگریمنٹ کے اور کچھ نہیں ہے - کیا دست ہے اسکو بھی تو روکیئے ہم لوگ تو بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک عزیز ساتھی کو اراداتاً بیٹھا لیا کہ اچھا ہے دل کی بھڑاس نکل جائے - لیکن کہاں تک جانا ہے اسکو -

*Not recorded.

†[] Transliteration in Arabic Script.

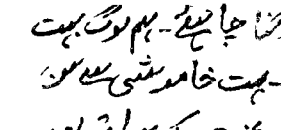

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आज़म खान जी, अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है। अगर समाप्त करना हो तो एक मिनट में समाप्त करें। ...**(व्यवधान)**

मोहम्मद आज़म खान: मैडम्, मैं दरसल धर्मनिर्पेक्ष और पंथनिर्पेक्ष पर ही बोल रहा था, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता बहुत विद्वान हैं ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका समय समाप्त हो गया है, माफ करें। अगर कांक्लूड करना है तो एक मिनट में कांक्लूड करें।

मोहम्मद आज़म खान: मैं यह कहना चाहता था कि इन सारे सवालों से इस देश के बहुत से लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं। जो बहुत कमजोर हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, जो बहुत दलित हैं। दलित का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि एक धर्म के मानने वाले ही लोग दलित हैं, बल्कि मुसलमान दलित, सिख दलित और दूसरे धर्मों में रहने वाले दलित उन्हें भी इस मुल्क में बराबर जीने, फलने-फूलने, खुशहाल रहने का हक होना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ें, लाकानुनियत के खिलाफ लड़े, क्रिमनलाइजेशन के खिलाफ लड़ें तो यह देश सही रास्ते पर जा सकता है। मैं अपना भाषण, अपनी बात इस अर्ज और इस माज़रत के साथ खत्म करता हूं कि जो लोग इस मुल्क में रह कर भी इस मुल्क को फर्गसजम के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं दरसल उनसे भी हम जैसे लोगों की समाजवादियों की बुनियादी लड़ाई है। हमें यही तय करना है कि इस देश का सही रास्ता क्या होगा।

क्या इस देश का रास्ता यह होगा कि सड़क पर चलने वाले शख्स के पेट में छुरा भोंक दिया जाए? उसका घर जला दिया जाए? उसकी इबादतगाहें लूट ली जाएं या इस देश में जो भी राजनीतिक या सामाजिक लोग होंगे, वे इस सवाल का जवाब देंगे कि भूखे को रोटी कैसे मिले? बरहनः जिस्म को कपड़ा कैसे मिले? जिसके पास रहने को मकान नहीं है, उसे मकान कैसे मिले? जिसके पास काम नहीं है उसे काम कैसे मिले? इन दो सोचों के बीच लड़ाई है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? इस संघर्ष में आखिर फतह किसकी होगी? लेकिन हमें उम्मीद है और उम्मीद इसलिए है कि जहां से बीच में मैंने अपनी बात शुरू की थी कि मायूसी और अंधेरे के उस दौर में कोई मुसलमान आगे बढ़ कर नहीं आया। आज के ज़माने में डॉ० ज़ाकिर हुसैन नहीं हैं, डॉ अंसारी नहीं हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं हैं, मौलाना शौकत अली नहीं हैं, हसरत मोहानी नहीं है, लियाकत अली नहीं हैं, ये सारे लोग नहीं है और इनके नहीं रहते हुए भी इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वे राम के भक्त भी हो सकते हैं, वे कृष्ण के भक्त भी हो सकते हैं। वे बहुत लंबे कद के न हों उनका कद बहुत छोटा हो सकता है लेकिन वे धोखा नहीं देते समाज को। वे अगर रोज़ी-रोटी से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं तो चाहे उर्दू के नाम पर लोगों को रोज़ी-रोटी देनी पड़े वे हज़ारों खानदानों को जीने का नया रास्ता दिखाते हैं। वे पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान पेंशन योजना लागू करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैडम्, एक मिनट पूरा हुआ या नहीं? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंन्हा): आप लोग शांत रहें ...**(व्यवधान)**... आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैडम, मैं इसी बात पर अपनी बात समाप्त करता हूं कि वह दिन दूर नहीं ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैडम्, आखिर समय की कोई सीमा है या नहीं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खान: वह कल दूर नहीं है, यह आपका अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैंने उनको समाप्त करने के लिए कह दिया है। ...आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खान: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं नहीं समझता हूं कि आपके अधिकार को हम में से कोई भी चैलेंज कर सकता हो और आपको कोई डायरेक्टिव यहां से जारी हो सकता हो कि आप किसको

बोलने देंगी और किसको नहीं बोलने देंगी आप कितना बोलने देंगी, यह अधिकार हमारा नहीं है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

यह आपका विवेक है कि आप किसको बोलने दें। लिहाज़ा इस पीठ से मुखातिब होते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम नाउम्मीदी के दौर से गुज़रे थे और उसी नाउम्मीदी के दौर में हमें जो उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी, उस किरण से ही मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि अगर किसी की जेब में एक फसाद की माचिस है, उसकी एक तीली से वह समाज के किसी एक छप्पर को अगर जलाने का काम करता है तो उस छप्पर से मिले हुए इस मुल्क में 90 करोड़ छप्पर हैं, वे सब जल जाएंगे, पूरा देश जलकर खाक हो जाएगा लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी जेब में जो तीली रखी है, उससे वह एक शमा रोशन करे और उस शमा से 90 करोड़ शमाएं रोशन हों और पूरा अंधेरा हिन्दुस्तान जगमगा उठे ऐसी ही शमा और ऐसे ही कल की उम्मीद में हम समझते है कि इन फासिस्टों की करारी हार होगी, समाजवाद सत्ता में आएगा और समाजवाद ही इस देश का कल बनेगा, धन्यवाद।

श्री नरेन्दर मोहन: उपसभाध्यक्ष जी, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अंततः बोलने का समय दिया। मैं जिस प्वाइंट आ फ आ र्डर को उठाना चाहता था, मैं केवल, यही कहना चाहता था...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): एक मिनट ज़रा ठहरिए। नरेश यादव जी, आप क्या कह रहे हैं!

श्री नरेश यादव: जहां तक मुझे याद है, मुझे बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के बाद जनता दल के बोलने की बारी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मैं लिस्ट के मुताबिक बुला रहा हूं। अभी नरेन्द्र मोहन जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। बड़ी उम्दा तकरीर शायद आज़म साहब ने दी है, उसकी मैं क्या कहूं? अच्छा होता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होती। ...(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: तारीफ की है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आग लगाने वाली माचिस है और इसे आप तारीफ कहते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अरे, आप ही की पार्टी के लोग बोल रहे है।

श्री नरेन्द्र मोहन: अफसोस यह है कि उन्होंने हिन्दू-मुसलमान की बात की। अफसोस है कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिससे साम्प्रदायिकता की बदबू आती है, अफसोस है कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिससे कि ज़ज्बात भड़के, मुल्क में बात लोगों तक पहुंचे कि नंगी औरतें घुमाई गई थीं, बलात्कार किया गया, डेढ़ साल के बच्चे...ऐसी-ऐसी बातें जिनको सुन कर अफसोस होता है कि उनका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कुछ भी लेना-देना नहीं है। अफसोस इस बात का है कि उन्होंने उस जमाने की बात भी की जब देश आजाद हुआ था। उस जमाने के हिन्दू-मुलसमानों की बात भी कर डाली। काश उन्हें मालूम होता, जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में लगभग साढ़े तीन करोड़ हिन्दू थे और आज वहां पर एक करोड़ हिन्दू भी नहीं हैं। मुझे अफसोस है कि उनके लिए वह कुछ कह पाते, उन शरणार्थियों के लिए, जो कश्मीर से भगा दिये गये और अपने देश में शरणार्थी होकर रह रहे हैं। लेकिन मुझे उसकी बात नहीं करनी है। मुझे तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात करनी है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विषय से हटकर बातें की जानी हैं, अगर भावनाएं भड़काकर, उत्तेजना भड़काकर बातें की जानी हैं तो यह कोई भी कर सकता है, यह बड़ी आसान बात है। मुश्किल बात यह है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कौन-सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, आज के हालात में देश का क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा हो तो शायद ठीक हो। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि वर्तमान भारत सरकार ने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया, वह झूठे आंकड़ों पर तैयार किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सही बातें देश को नहीं बतायीं गयीं और इसीलिए जिसकी बैसाखी पर यह सरकार चल रही है, कांग्रेस सरकार, उसने भी इसकी आलोचना की है। मुझे अफसोस है कि राष्ट्रपति की यह विवशता है कि राष्ट्रपति जी को सरकार कुछ भी कहने के लिए दे दे, वह अपने सरकार के समर्थन में गलत-सही आंकड़े जरूर कहेंगे और गलत सही बातें स्वीकार करके अपनी ओर से कहें, यह भारतीय संविधान की कमजोरी है और मुझे इस बात का अफसोस है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे राष्ट्रपति जी कांग्रेस की बात करते थे और जब संयुक्त मोर्चा की सरकार आयी जिसकी हरेक पार्टी के घोषणा पत्र में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना है, उसकी

उन नीतियों की तारीफ हमारे राष्ट्रपति जी करने लगे, यह भारतीय संविधान की कमजोरी है, पता नहीं ठीक हो पाएगी या नहीं। लेकिन राष्ट्रपति की तो विवशता हो सकती है, संसद की विवशता नहीं है कि वह गलत बातों को स्वीकार करे या राज्य सभा की विवशता नहीं है कि वह पाखंड को सहन करे। यह हमारी विवशता नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कितनी गलत बातें हैं, कितनी कमजोरियां हैं तो शायद जो मेरे साथी लोग भाषण की सराहना कर रहे हैं, जो धन्यवाद का प्रस्ताव ला रहे हैं, उन्हें वास्तविकता की जानकारी हो जायेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जोर दिया गया है कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने की बात उनके मिनिमम प्रोग्राम में भी कही गयी है। लेकिन जब हमें यह बात कही गयी तो कहा गया कि अनुच्छेद 356 को यथाशीघ्र हम हटा देंगे, हम उसमें परिवर्तन कर देंगे और इसलिए परिवर्तन करेंगे कि कोई उसका दुरुपयोग न करने पाए। यह बात मिनिमम प्रोग्राम में लिखी हुई है। वह मेरे पास है और मैं उन लफ्जों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि

> "The scope of article 356 has been interpreted and circumscribed by recent decisions of the Supreme Court. Article 356 will be amended to reflect these decisions and to prevent the misuse of this article."

This has been recognised.

यह लिखने के बाद नौ महीने हो गये, उसमें क्या किया गया? एक कमेटी बना दी गयी। कमेटी बनाने की बात तो इसमें नहीं लिखी गयी थी। अगर इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कोई कमेटी बनाने की बात लिखी गयी होती, कोई पुनर्विचार करने की बात लिखी गयी होती तो बात समझ में आती थी। यह सरकार तो अपने वायदे से भी मुकर गयी, अपने न्यूनतम कार्यक्रम से भी मुकर गयी और इस पाखंडी सरकार ने क्या किया कि धारा 356 का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायकों को आज तक शपथ भी नहीं लेने दी गयी है। इसी 356 के दुरुपयोग के बारे में, हमारे माननीय मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठे हुए हैं, वह खुद पिछले दिनों अपने भाषण में उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन की स्थिति ठीक नहीं है, वहां प्रशासन की स्थिति बिगड़ चुकी है, यह कह चुके हैं।

यही नहीं हमारे देश के गृह मंत्री ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं है। शासन और व्यवस्था नाम को वहां कोई चीज नहीं है। अब, काश इस सरकार को थोड़ी सी शर्म होती, उनके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी होती, थोड़ी सी नैतिकता होती तो जरूर इस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती। आज उ० प्र० के गवर्नर की हिम्मत देखिए, उसने देश के गृह मंत्री के बयान को, सदन में दिए गए बयान को चुनौती दे दी और कहा कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। मेरी रक्षा तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। यह कैसी स्थिति इस देश की है? क्या गृह मंत्री इतने कमजोर हो गए हैं? उपसभाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बहुत बातों में एकता नहीं है। दोनों में नाइत्तफाकी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सार्वजनिक रूप से हमारे देश के गृह मंत्री की इस तरह से बेइज्जती की जाए। हमारे देश के गृह मंत्री की इस तरह से छीछालेदर की जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है और वह भी कौन करे? एक राज्यपाल करे। उसकी हिम्मत देखिए, उसकी जुबान देखिए। लेकिन उस पर भी सदन चुप है, मौन है। यह सदन मौन है और विशेषरूप से इस सदन का वह पक्ष मौन है जिसके हाथ में सत्ता है। इतनी बड़ी कमजोरी क्यों, यह नपुंसकता क्यों? आज अगर सत्ता पक्ष की नपुंसकता पर मैं प्रहार कर रहा हूं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। यह देश के गृह मंत्री की प्रतिष्ठा की बात है। ...(व्यवधान)...

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): क्या किसी राज्यपाल के आचरण पर हम यहां चर्चा कर सकते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वह किसी के आचरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे नपुंसकता की बात कर रहे है। ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: जो बातें राज्यपाल ने कही हैं ...(व्यवधान)... वे उस बात को कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): शास्त्री जी, आप पुराने सदस्य है सदन के ...(व्यवधान)...

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, this issue was raised during the Zero Hour by Syed Sibtey Razi. *(Interruption)*

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): शास्त्री जी आप इतने विद्वान आदमी है आपको ऐसे (व्यवधान)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: उन्होंने वही कहा जो राज्यपाल ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपकी बात हो चुकी है ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु: नपुंसकता गलत शब्द है। इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरीफ उद्दीन शारिक: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): This will not go on record. *(Interuptions)* Nothing will go on record.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: *

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिये। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, मैंने बोल्ड दिया है। नरेन्दर मोहन जी के भाषण के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन: उपसभाध्यक्ष जी, मेरा 10 मिनट का समय जो इसमें निकल गया वह कृपा करके मेरा न काटें। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं यह समय मेरा वापस करा दिया जाए। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप बोलिए। *(Interruptions)* We will go through the record and if there is anything, we will expunge it.

श्री नरेन्द्र मोहन: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चीफ इंजिक्युटिव ने भारत के गृह मंत्री की भद्दी आलोचना की, बहुत भद्दी है जिसकी चर्चा श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी ने भी की। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं यह कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस ने अच्छी बात की। कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मामले में गवर्नर की धज्जियां उड़ाई, वह उचित बात थी। मैं उसके साथ अपने को जोड़ता हूं। लेकिन सवाल यह है कि केवल उतना ही नहीं है, उससे ज्यादा हुआ है। अभी सी०बी०आई० ने कहा कि जो आयुर्वेदिक दवाओं का घोटाला हुआ है उसकी जांच करने की अनुमति मांगी जो अपराधी हैं उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति उनको दे दी जाए यह मांग भी की। यह सरकार कह रही है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है। यह चिंता देखिये। सी०बी०आई० कह रही है कि हमको मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी जाए और कहा जाता है कि नहीं हम आपको मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। यह किसी के इशारे पर हो रहा है? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए चिंतित है या केवल उसका राजनीतिकरण कर रही है। यह माजरा क्या है? मैं जानना चाहता हूं। इण्डियन बैंक के एक्स चेयरमैन गोपाल कृष्णन के मामले में सी०बी०आई० ने बार बार रिज़र्व बैंक से कहा कि हमें उनके सारे कागज़ात दे दिये जाएं और भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक पर दबाव बनाया कि कोई कागज़ात सी०बी०आई० को न दिये जाएं। यह सरकार कह रही है कि उसे भ्रष्टाचार की बड़ी चिंता है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। इससे बड़े पाखंड की ओर क्या बात हो सकती है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जिसकी सरकार है, जिस दल का प्रधानमंत्री है उस दल का अध्यक्ष सी०बी०आई० को धमकी देता है और कहता है मैं निपट लूंगा, मैं बिहार की, पटना की सड़कों पर निपट लूंगा सी०बी०आई० से। एक नहीं अनेक भाषण देता है। अफसोस की बात है और वह सरकार कहती है कि उसे भ्रष्टाचार की बड़ी चिंता है। यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सर्वोच्च न्यायालय की ताकत अभी बाकी है, नहीं तो इस सरकार के लोगों ने कब का इस देश का बिस्तर गोल कर दिया होता। 9 महीने में बहुत कुछ कर लिया होता। लेकिन इन 9 महीनों में सिवाय भ्रष्टाचार के बढ़ाने के इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। देश में खाद्यान्न की कमी नहीं थी देश के फूड कारपोरेशन के गोदामों में खाद्यान्न भरा हुआ रखा था। यह आंकड़े बता रहे हैं। मंत्री बैठे हैं, खंडन कर दें इस बात का लेकिन खाद्यान्न होने के बाद भी 20 लाख टन गेहूं मंगाया गया और किन दरों पर मंगाया गया, जो दरें बाज़ार से ज्यादा थी। क्या हुआ, यह कैसे हुआ! गोदामों में गल्ला भरा हुआ रखा रहे, मूल्य से ज्यादा पर मंगा लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से ज्यादा दे कर अनाज मंगाया जाए। यह क्यों हुआ? क्या इसमें भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध नहीं आती? और मज़ेदार बात बताऊंगा, खंडन कर सकते हों तो करें, मैं चुनौती देता हूं। खाद्य मंत्री से बिना पूछे, उन्हें बिना विश्वास में लिये, यह सौदा किया गया। मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार के मंत्रियों पर जिन्होंने यह सौदा किया। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। खाद्य मंत्री को विश्वास में लिया ही नहीं गया, एक दिन भी विश्वास में नहीं लिया गया, एक मिनट भी विश्वास में नहीं लिया गया और लेटर आफ क्रेडिट खोल दिया गया। उनकी जानकारी में यह बात नहीं थी कि इतना बड़ा सौदा होने जा रहा है। इस तरह से सरकार काम

*Expunged as ordered by the Chair.

करती है, यह भ्रष्टाचार को दूर करेगी, यह संभव नहीं हो सकता।

प्रधान मंत्री निर्देश देते हैं कि सी०बी०आई० किसी भी मंत्री और भूतपूर्व मंत्री की जांच नहीं करेगी जब तक उनसे अनुमति न ले ली जाए। खंडन करिए। कोई खड़ा होकर खंडन करे। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। क्या ऐसा निर्देश प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं गया। हो हिम्मत करे खंडन करिए और यह सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर चिंता है इसको। कैसी चिंता है यह? यह सरकार तो यह कहती है कि मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अगर कोई जांच करनी है तो पहले उनकी लिखित अनुमति ले ली जाए। यह बड़े अफसोस की बात है। और देखिए, मैं इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, और भी कहना चाहता हूं। इनको जब सर्वोच्च न्यायालय के जजों से भी कुछ खतरा लग रहा है। ये चाहते हैं कि जजों की नियुक्तियों में भी कुछ घपलेबाजी कर सकें। यह बड़ी अजीब बात है। खुले आम चर्चा हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्तियों में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए....(**व्यवधान**)

श्री वसीम अहमद: यह एलीगेशन बिल्कुल बेसलेस है। आप कैसी बात कर रहे है। यह इतना बेसलेस एलीगेशन आप लगा रहे हैं...(**व्यवधान**)

SHRI JOHN F. FERNANDES: There was a statement from the Law Minister.

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्वाइंट आफ आर्डर क्या है।

SHRI NILOTPAL BASU: The point of order is this. He is levelling certain allegations against responsible members of the Government on the floor of the House. I want to know whether he has given any notice to the Government before levelling these allegations or not. . . (*Interruptions*). . .

SHRI NARENDERA MOHAN: I want them to refute. I want them to refute. I am levelling certain allegations consciously. . . . (*Interruptions*). . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नरेन्द्र मोहन जी सुनिए..

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDRA K. ALAGH): Sir, all I am saying is that the hon. Member has no idea of the way imports are planned, the working of the Cabinet Committee on Prices and so on where all these things are discussed. These are wild allegations which I. . . (*Interruptions*). . .

SHRI NARENDRA MOHAN: These are not wild allegation. I want them to refute whether the Food Minister had been consulted or not.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): बिल्कुल बेसलेस एलीगेशन लगा रहे हैं।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir. . . (*Interruptions*). . .

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You have made your point.

नरेन्द्र मोहन जी सुनिए। एक तो भाषण देते समय थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो वह अलहिदा बात है। आप "खंडन करो" "खंडन करो", करके दूसरों को ऐसे प्रोवोक भी मत करिए। आप भाषण दीजिए, एक और दूसरी तरफ अगर वे अखंडन करते हैं तो सुन लीजिए ...(**व्यवधान**) अब ऐसा है कि यहां सदन में हम लोग जब कुछ बात करते हैं अगर कोई आपको किसी के बारे में अभियोग लगाना है, या तो उसकी नोटिस देनी चाहिए या तो कुछ सबसटेंशिएट करना चाहिए। आप भाषण दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं लेकिन डोंट मेक एलीगेशंस।

श्री नरेन्द्र मोहन: अब सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्तियों के बारे में....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इसी के बारे में बोल रहा हूं। वह जो भूट गया वह अलहिदा बात है। अब जजों के रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आप बोलते हैं तो ऐसी नोटिस दें, अगर ऐसी इन्फारमेशन आपके पास है, वरना इस सदन में हम गंभीरता से लेते हैं किसी भी बात को।

श्री नरेन्द्र मोहन: उपसभाध्यक्षजी, सर्वोच्च न्यायालय के जजों...(**व्यवधान**)

That news has been published in all the newspapers. I have got the cutting, I can show it to you. I am referring to various news-items published and. . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): A news-item published cannot

be produced as evidence here. If you have certain other things, you can.. . . (*Interruptions*). . .

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Sir, there was a proposal which had been publicly discussed that the *Gupta* Judgement should be reversed and the power to appoint judges should be taken over by the Executive. The hon. Member is entitled to comment on it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Jethmalaniji, he did not speak in the way you spoke. He was levelling certain allegations.

SHRI NARENDRA MOHAN: No, no. I am not levelling any allegation.. . . (*Interruptions*). .

I was not levelling any allegations.. . . (*Interruptions*). . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He said,

नियुक्तियों के बारे में घपले हो रहे हैं . . (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि...

what he is saying is different.

SHRI NARENDRA MOHAN: How can this Government really eradicate corruption? What are they? They want their henchmen.. . . (*Interruptions*). . .

SHRI JOHN. F. FERNANDES: Sir, I want to clarify it. The Law Minister made a statement in Goa. In his statement he said that a committee will be appointed for the appointment of judges in the PMO. That is the declared policy of the Government. . . (*Interruptions*). . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अच्छा, अब इसे कंटीन्यू करने से पहले. . .

श्री नरेन्द्र मोहन: हां साहब, मुझे तो अभी कम से कम एक घंटा बोलना है. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप एक घंटा बोलें। लेकिन सदन का भी तो समय है। आपका समय है। आपका समय समाप्त नहीं हुआ है. . .

श्री नरेन्द्र मोहन: तो कल कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सुनिए मेरी बात। पांच बजे हमें एडर्जन करना है। कल होगा यह तो शायद ठीक नहीं। कल तो शुक्रवार है। जब नेक्स्ट डे या जिस रोज डिसक्शन होगा तो उस रोज आप बोलेंगे। इसके बाद फिर कंटीन्यू करेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: ठीक है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): उससे पहले अभी एक स्टेटमेंट है कम्युनिकेशंस मिनिस्टर का। चूंकि पांच बजे हमें एडर्जन करना है तो वे ले कर सकते हैं 9 टेबुल पर उसके बाद प्रेजीडेंट एड्रेस बाद में लिया जा सकता है।

5.00 P.M.
STATEMENT BY MINISTER

Village Public Telephones

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं।

यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय संचार मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं इसे भगवान की कृपा मानता हूं। मुझे आप यह अखबारों में पढ़ने को मिला है कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने टेलिफोन देने का हम लोगों का जो विशेषाधिकार है, वह एक अप्रैल से खारिज कर दिया है। मैं संचार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक अप्रैल तक तो हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? अगर एक अप्रैल के भीतर हम जितने टेलिफोन दे सकते हैं दे दें, तब तो आप को आपत्ति नहीं होगी? इस विषय में कृपया आप स्पष्टीकरण दें ... (व्यवधान) ... मैं आप सब के लिए पूछ रहा हूं। यह मेरे अकेले का नहीं, सब का सवाल है। आप को तो प्रशंसा करनी चाहिए। ... (व्यवधान) ...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमान्, कल मैं लोकसभा में बैठा हुआ था जब माननीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्देश दिया था। निर्देश देने के पूर्व मुझे किसी प्रकार की